राष्ट्रीय

छात्रशक्ति

वर्ष 45 ■ अंक 03 ■ जून 2023 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 40

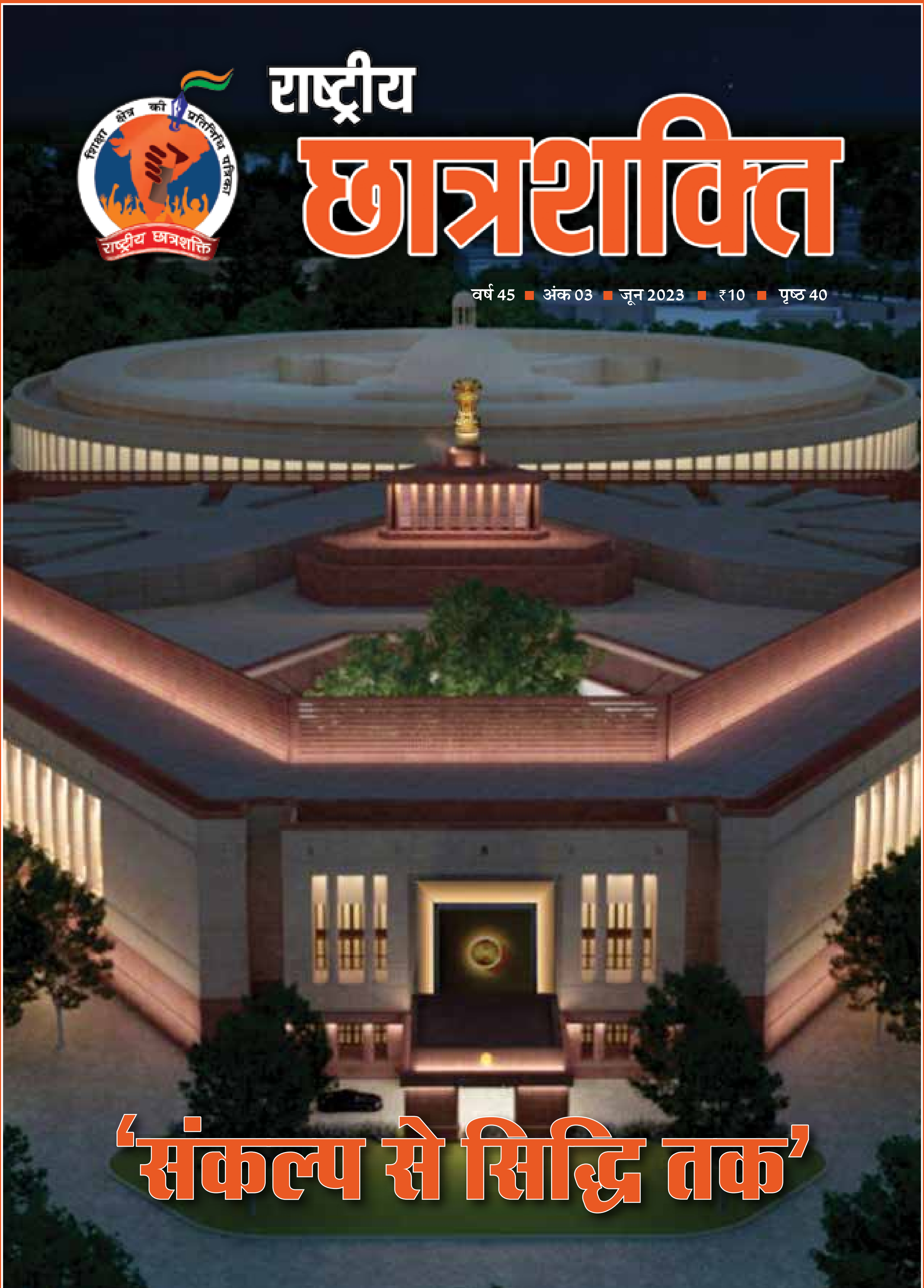

'संकल्प से सिद्धि तक'

अभाविप गोरक्ष प्रांत द्वारा मऊ में आयोजित प्रांत छात्रा सम्मेलन को संबोधित करती अभाविप प्रांत अध्यक्ष प्रा. सुषमा पांडेय, मंचासीन हैं उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी, अभाविप राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह व अन्य

अभाविप झारखंड द्वारा आयोजित एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ करते विकास भारती के सचिव अशोक भगत, अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद नायक, खेल गतिविधि संयोजक कुमारी पल्लवी गाड़ी, अभाविप प्रदेश मंत्री सोमनाथ भगत व अन्य

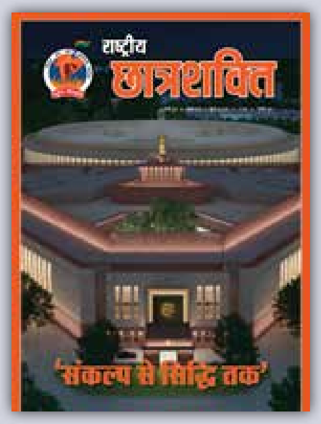

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 45, अंक 03
जून 2023

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

अबकी बार

05 राष्ट्र को समर्पित किया गया भारत का अपना संसद भवन

'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे भारत को अंततः अपना संसद भवन मिल गया। नए संसद भवन को 'भारत का अपना संसद भवन' इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आजादी मिलने के बाद देश की जनता ने ...

संपादकीय	04
अभाविप, आपातकाल और पुराना संसद भवन	09
एनसीईआरटी की पुस्तकों से नाम हटाने की मांग को शिक्षाविदों ने बौद्धिक अहंकार बताया	12
THE PARADOX OF SUBVERTING DEMOCRACY TO ESTABLISH "DEMOCRACY"	14
अभाविप की चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक पुणे में संपन्न	16
नागरिक अभिनंदन समारोह में अभाविप के कार्यों की सराहना	21
केन्द्रीय कार्यसमिति, आयाम तथा प्रांत कोषाध्यक्ष बैठक का आयोजन	23
छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित 'जाणता राजा' नाट्य का मंचन	24
प्रस्ताव 01/शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता पर ध्यान दें प्रदेश सरकारें एवं विश्वविद्यालय प्रशासन	25
अभाविप गोरक्ष प्रांत द्वारा मऊ में छात्रा सम्मेलन का आयोजन	26
प्रस्ताव 02/आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन के केंद्र बनें परिसर	27
प्रस्ताव 03/भारत विरोधी वैश्विक षड्यंत्रकारी ताक्तों को परास्त करे युवा	28
राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे का निधन : अभाविप	29
प्रस्ताव 04/स्व-आधारित व्यवस्था निर्माण हेतु समाज हो अग्रसर	30
"आत्म प्रेरणा से पैदा होता है सेवा भाव"	31
ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों की सहायता में जुटे अभाविप कार्यकर्ता	32
आर्थिक अभाव नहीं बन सकता है शिक्षा में बाधा	33
झारखंड अभाविप द्वारा जनजातीय छात्रों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन	34
श्मशान के करीब पहुंच गई है बंगाल की शिक्षा व्यवस्था : मिथुन चक्रवर्ती	35
अभाविप के संघर्षों ने लाया रंग, जेएनयू में चार साल बाद होंगे छात्रसंघ चुनाव	36
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अभाविप का विरोध-प्रदर्शन	37
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद, अभाविप ने खोला मोर्चा	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

राहुल गाँधी के बाद अब आप सरकार की मंत्री आतिशी ने विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया है। कैम्ब्रिज इंडिया कान्फ्रेंस में बोलते हुए आतिशी ने दावा किया कि भारत में रोजाना 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं।

भारत के बाहर जाकर भारत की छवि खराब करने का यह जुनून अनेक विपक्षी नेताओं में दिख रहा है। ऐसी किसी भी घटना के बाद उनके दल के लोग इस पर खेद व्यक्त करने के स्थान पर उनके गलत और तर्कहीन बयानों का बचाव करते नजर आते हैं। वे यह भूल जाते है कि भारत उनका भी देश है और अपने देश की जगहंसाई कराने में उनका अपना भी अपमान है। दुर्भाग्य यह है कि राजनैतिक विद्वेष से पीड़ित यह राजनेता अपने इस अपमान में भी आनंद की अनुभूति करते हैं।

2014 में जब से केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय विचार को सामने रखकर निर्णय लेने का क्रम प्रारंभ हुआ, तभी से सत्ता से बेदखल हुये समूह का यह रूदाली गायन चल रहा है। गुलामी के प्रतीकों को हटाने की हर कोशिश का विपक्ष द्वारा जिस प्रकार विरोध किया जाता है उससे संदेह उत्पन्न होता है कि वे विदेशी आक्रांताओं की निशानियों को ही तो अपनी विरासत नहीं मान बैठे हैं?

विरोध की इन घटनाओं में भी एक पैटर्न दिखायी देता है। यह घटनाऐं तेजी से बढ़ती हैं जब लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव निकट आते हैं। 2019 के चुनाव के पहले अवार्ड वापसी का नाटक हुआ था। 2024 के चुनावों की आहट के साथ एनसीईआरटी की किताबों से नाम वापस लेने का अभियान प्रारंभ हो चुका है। बहस इस पर नहीं है कि कथित संशोधनों में कौन से तथ्यों को दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जिद यह है कि जो दो दशक पहले लिख दिया गया है उसे बदलना असंभव है। निस्संदेह यह व्यवहार गैर अकादमिक और अस्वीकार्य है।

यह विडम्बना ही है कि ऐसी सभी राजनैतिक संघर्षों का अखाड़ा शिक्षा क्षेत्र को बना दिया जाता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों, दोनों के सामने यह चुनौती बनी रहती है कि साम्प्रदायिक और राजनैतिक दुष्प्रचारों को दूर कर शिक्षा को कैसे तथ्यपरक और मूल्य आधारित बनाया जा सके।

विडम्बना यह भी है कि यह राजनैतिक विषवमन लोकतंत्र के नाम पर किया जा रहा है। इसके विपरीत यह स्थापित तथ्य है कि 26 जून 1975 को देश में जब लोकतंत्र की हत्या की कोशिश हुई तो आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग लोकतंत्र विरोधी शक्तियों के साथ थे, वहीं अभाविप जैसे संगठनों के संघर्ष के बल पर लोकतंत्र की बहाली संभव हो सकी थी।

नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर तो है ही, यह उल्लेखनीय है कि इस पर गुलामी की छाया भी नहीं है। इसका विरोध कर लोग अपनी संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन ही कर रहे हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित्

आपका,

संपादक

नए संसद भवन में लोकसभा

फोटो: पत्र-सूचना कार्यालय

राष्ट्र को समर्पित भारत का अपना संसद भवन

| संजय दीक्षित |

'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे भारत को अंततः अपना संसद भवन मिल गया। नए संसद भवन को 'भारत का अपना संसद भवन' इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की जनता ने 75 वर्ष तक अपनी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन जिस संसद भवन से चलते हुए देखा, उसका निर्माण ब्रिटिश सत्ता ने अपने हितों के अनुरूप किया था। 1927 में बनकर तैयार हुए उस भवन को स्वतंत्रता से पहले तक 'हाउस ऑफ़ पार्लियामेंट' कहा जाता था और यहां पर ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद कार्यरत थी।

लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पश्चात भारत को अपना संसद भवन मिल गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 28 मई को पूर्ण वैदिक विधि-विधान से राष्ट्र को समर्पित किया। 'लोकतंत्र के भारतीय मंदिर' में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना होना भी एक अद्भुत एवं ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली स्थित नया संसद भवन केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के पुराने हो चुके भवनों के स्थान पर नए भवनों का निर्माण करना है। इस परियोजना में केंद्र सरकार लगभग 14 हजार करोड़ की धनराशि खर्च करेगी।

त्रिकोण के आकार में बनाया गया नया संसद भवन, भारत की प्राचीन सनातन हिन्दू संस्कृति की दृष्टि से "त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा-विष्णु-महेश" की संकल्पना को तो साकार करता ही है, साथ ही सत्व-रजस-तमस को भी परिभाषित करता है। नया संसद भवन में एक त्रिभुज के साथ एक गोलाकार आकृति भी नजर आती है, जिसे शिव और शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नई संसद के वास्तुकार बिमल पटेल के अनुसार नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह त्रिकोणीय भूखंड पर बना है। इसका तिकोना होना देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को भी दर्शाता है।

पवित्र सेन्गोल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं संत फोटो: पत्र सूचना कार्यालय

अमृत काल का सांस्कृतिक प्रतीक : पवित्र सेन्गोल

स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद निर्मित भारत की अपनी रचना अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र दंड सेन्गोल की स्थापना का निर्णय निश्चय ही ऐतिहासिक है। भारत की प्राचीन सनातन हिन्दू परंपरा में जब कोई शासक अपने पद की शपथ लेता था, उस समय धर्म और न्याय पूर्ण शासन की अपेक्षाओं के प्रतीक के रूप में राजगुरु की ओर से पवित्र दंड सेन्गोल दिया जाता था। यह पवित्र दंड शासक को हर समय यह याद दिलाता था कि धर्म और न्याय से विमुख होने की स्थिति में उसे भी "दंड" का सामना करना पड़ेगा। प्राचीन परंपरा का आधुनिक भारत में पुनः प्रतिष्ठित होना निश्चय ही देश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही संसद भवन में पवित्र दंड की स्थापना "अमृत काल के सांस्कृतिक प्रतीक" के रूप में देखी जा सकती है।

वैसे तो संसद भवन में पवित्र दंड सेन्गोल की स्थापना वास्तव में 15 अगस्त 1947 में की जानी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। जानकारी के अनुसार 14 अगस्त, 1947 की रात को वह एक विशेष अवसर था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई आधीनम (मठ) से विशेष रूप से पधारे आधीनमों (पुरोहितों) से पवित्र दंड सेन्गोल ग्रहण किया था। वह वह क्षण था, जब ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने उसे पुराने संसद भवन में स्थापित करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया।

लेकिन 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे देश में दशकों बाद 'अमृत काल के सांस्कृतिक

प्रतीक' के रूप में पवित्र दंड "सेन्गोल" की स्थापना की गयी है। पवित्र दंड "सेन्गोल" का अर्थ बहुत गूढ़ है। जानकारों के अनुसार ''सेन्गोल" शब्द तमिल शब्द "सेम्मई" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "नीति-परायणता"। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य आधीनम (पुरोहितों) का आशीर्वाद प्राप्त है। 'न्याय' के प्रेक्षक के रूप में, अपनी अटल दृष्टि के साथ देखते हुए, हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान हैं। सेन्गोल को ग्रहण करने वाले शासक को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का 'आदेश' (तमिल में 'आणई') होता है और लोगों की सेवा करने के लिए चुने गए लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को, कर्तव्यपथ का, सेवापथ का, राष्ट्रपथ का प्रतीक माना जाता था।

स्वतंत्रता से पूर्व तमिलनाडु सरकार ने 2021-22 के 'हिन्दू रिलिजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट'- हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर एंड सीई) के नीतिपत्र में राज्य के मठों द्वारा निभाई गई भूमिका को गर्व से प्रकाशित किया है। इस दस्तावेज़ के पैरा-24 में मठों द्वारा शाही परामर्शदाता के रूप में निभाई गई भूमिका पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। यह ऐतिहासिक योजना आधीनम के अध्यक्षों से विचार-विमर्श करके बनाई गई थी।

नए संसद भवन में पवित्र दंड "सेन्गोल की स्थापना के अवसर पर सभी 20 आधीनम के अध्यक्ष प्रमुखता से उपस्थित रहे। हिन्दू विधि-विधान के साथ हुए पवित्र अनुष्ठान के बाद पवित्र दंड "सेन्गोल" प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेन्गोल को पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित किया। समारोह में 96 साल के श्री वुम्मिडी बंगारु चेट्टी भी सम्मिलित हुए जो इसके निर्माण से जुड़े रहे हैं।

'अमृत काल के सांस्कृतिक प्रतीक' के रूप में पवित्र दंड सेन्गोल को देश की जनता की असीम आशा, अनंत संभावनाओं और एक सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण संकल्प के रूप में देखा जा सकता है। यह अमृतकाल का वह प्रतिबिंब भी होगा, जो नए भारत को विश्व में अपने यथोचित स्थान को ग्रहण करने के गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। ■

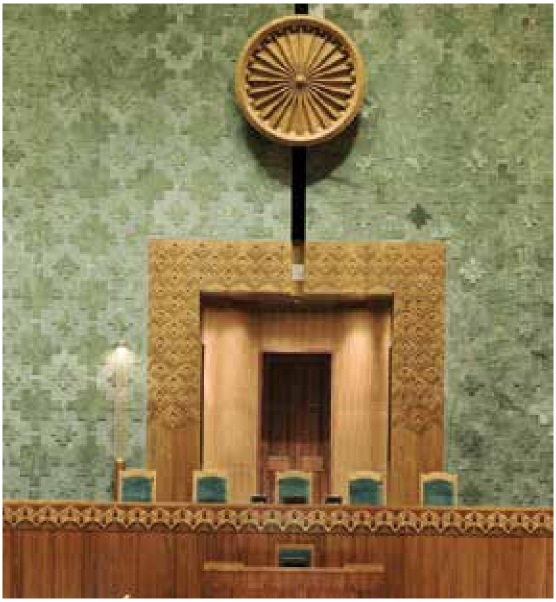

नया सेंट्रल हॉल *फोटो: पत्र सूचना कार्यालय*

भारत का अपना संसद भवन लगभग 65000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 में प्रारम्भ हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी समय-समय पर यह कहते रहे हैं कि जिस कार्य का वह शिलान्यास करते हैं उस कार्य के पूरा होने के बाद उसे वह ही राष्ट्र को समर्पित करते हैं। यह संकल्प से सिद्धि का ही उदाहरण है। नई संसद का शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया, जो इसका ताजा उदाहरण है। कोविड महामारी के दौरान जब पूरा देश थम गया था, उस समय भी संसद भवन का निर्माण कार्य जारी रहा। 971 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नया संसद भवन अपने आप में कई विशेषताओं और आकर्षण को समेटे हुए है। नए संसद भवन में अत्याधुनिक सुविधाएं और हाईटेक व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति पर बनी नई लोकसभा में 888 सीटें और राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति पर बनी राज्यसभा में 348 सीटें मौजूद हैं। भवन में

नई राज्यसभा *फोटो: पत्र सूचना कार्यालय*

संयुक्त सत्र के लिए 1,272 सीटों वाला एक हॉल भी बनाया गया है। नए संसद भवन के संविधान हॉल को भवन के मध्य में बनाकर इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया है। साथ ही इस हॉल में संविधान की मूल प्रति को भी रखा गया है।

नए संसद भवन की संरचना 'प्लैटिनम-रेटेड ग्रीन बिल्डिंग' के रूप में है, जो पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति भारत के समर्पण को प्रदर्शित करता है। साथ ही नया संसद भवन क्षेत्रीय कलाओं, शिल्पों एवं सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करते हुए आधुनिक भारत की जीवंतता और विविधता को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है। नए संसद भवन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी गई है। सार्वजनिक प्रवेश के द्वार तीन दीर्घाओं की ओर ले जाते हैं, उनमे पहली संगीत गैलरी है, जो भारत के नृत्य, गीत एवं संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करती है। दूसरी स्थापत्य गैलरी है, जो देश की स्थापत्य विरासत को दर्शाती है और तीसरी शिल्प गैलरी है, जो विभिन्न राज्यों की विशिष्ट हस्तकला परंपराओं को प्रदर्शित करती है।

आधुनिक व्यवस्थाओं से युक्त नए संसद भवन में सभी सांसदों के लिए अलग-अलग कार्यालय तथा कार्यालय को पेपरलेस बनाने के लिए डिजिटल इंटरफेस से लैस किया गया है। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग का स्थान भी उपलब्ध कराया गया। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में प्रभावी विधायी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये एक डिजीटल मतदान तंत्र, सु-अभियांत्रिक ध्वनिकी और अत्याधुनिक दृश्य-श्रव्य तंत्रों की स्थापना की गई है।

चार मंजिला नए संसद भवन में देश के अलग-अलग हिस्सों की जो विविधता है, उन सभी को समाहित किया गया है। इसमें राजस्थान का ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। लकड़ी का कार्य महाराष्ट्र से लकड़ी से किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही के कारीगरों के बने कालीनों से भूमि को सजाया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि सम्पूर्ण भवन 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाता है। संसद भवन के निर्माण कार्य में लगभग 60 हजार श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ और उनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है। विश्व में शायद ऐसा पहली बार हुआ है, जब संसद भवन के निर्माण करने वाले श्रमिकों का योगदान अमर हो गया है।

राष्ट्र को समर्पित करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वाहन कहीं से भी गलत नहीं लगता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद, एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून, भारत को विकसित भारत बनाएंगे। संसद का यह नया भवन, नए भारत के सृजन का आधार बनेगा, जो एक समृद्ध सशक्त और विकसित भारत, नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्यपथ पर और सशक्त होकर चलने वाले भारत के रूप में सभी देशों का मार्गदर्शन करेगा। ■

अभाविप, आपातकाल और पुराना संसद भवन

| अजीत कुमार सिंह |

हर वर्ष जून माह में आपातकाल की यादें ताजा हो जाती है। 48 वर्ष पूर्व देश की जनता ने जाना कि लोकतंत्र में किस प्रकार सत्ता के लिए इंदिरा गांधी (पूर्व प्रधानमंत्री) ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद पर दबाव बनाकर आपातकाल के प्रस्ताव पर रात में हस्ताक्षर कराए और उसके बाद पूरी कैबिनेट पर दबाव बनाकर प्रस्ताव को पारित करा लिया। यह सब 25-26 जून 1975 की रात में हुआ। देश की जनता उस समय सो रही थी। लेकिन 26 जून की सुबह जब सभी की आंख खुली, तब उन्हें पता चला कि सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता को बंधक बनाकर, सत्ता का दुरूपयोग कैसे किया जाता है।

26 जून को पूरा देश में भयाक्रांत करने वाले वातावरण विद्यमान था। भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की पदचाप से सारा वातावरण सहम रहा था। मध्यरात्रि में ही प्रमुख विपक्षी नेता, लोक संघर्ष समिति के सब सदस्य, छात्र संघर्ष समिति के नेतागण, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रमुख कार्यकर्ता, आलोचक पत्रकार-संपादक एवं कांग्रेस में ही इंदिरा गांधी की कार्यशैली से मतभेद रखने वाले नेता, सभी गिरफ्तार किए जा चुके थे। नागरिकों की स्वतंत्रता पर तानाशाही के ताले लटक रहे थे। समाचार पत्रों में प्रेस सेंसरशिप लागू करके आम नागरिकों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निलंबित किए जा चुके थे।

इस प्रकार 26 जून को सारा देश एक कारागार में बदल गया। देश के सभी हिस्सों में धारा-144 लागू हो चुकी थी। कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ, अनेक समाचार पत्रों की बिजली काट दी गयी और जो समाचार पत्र छप चुके थे, उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पुलिस को असीमित पर गैरकानूनी अधिकार मिल गए थे, तो वह

किसी को भी उनके घर, कार्यालय, छात्रावास और कॉलेज से गिरफ्तार करके ले जा रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित छब्बीस संगठनों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल का विरोध करने के साथ ही जेल में बंद किए जा रहे लोगों के परिवार के बीच अपना काम प्रारम्भ कर दिया। अभाविप पर कठोर प्रतिबन्ध नहीं लगे थे, लेकिन उसे भी तत्कालीन व्यवस्था में उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है।

26 जून की सुबह अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय छात्र संघर्ष समिति के संयोजक स्वर्गीय अरुण जेटली के नेतृत्व में आपातकाल की घोषणा के विरुद्ध पहली आवाज उठी। उपकुलपति कार्यालय के सामने छात्रों के एक समूह को सम्बोधित करते हुए जेटली को मीसा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन समय में मीसा अर्थात आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, वह कानून था, जिसे 1971 में संसद द्वारा पारित करकर इंदिरा गांधी ने देश में लागू किया था। इस

पुराना संसद भवन : एक नजर

पुराने संसद भवन ने औपनिवेशिक शासन से लेकर स्वतन्त्र भारत में कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं। संसद के मौजूदा पुराने भवन ने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया है और भारत के संविधान को अपनाया है। पुराना संसद भवन ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई एक औपनिवेशिक युग की इमारत है, जिसके निर्माण में छह वर्ष (1921-1927) लगे। मूल रूप से "हाउस ऑफ़ पार्लियामेंट" कहे जाने वाले इस इमारत में अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में दो और मंजिलें जोड़ी गईं। आधुनिक संसद के उद्देश्य के अनुरूप इस इमारत को बड़े पैमाने पर संशोधित किया जाना था।

पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू किया गया और वर्ष 1927 में इसे प्रयोग में लाया गया। यह लगभग 100 वर्ष पुराना एक विरासत ग्रेड-। भवन है। संसद भवन के मूल डिजाइन का कोई अभिलेख या दस्तावेज नहीं है। इसलिए यहां नए निर्माण और संशोधन अस्थायी रूप से किए गए। उदाहरण के लिए, भवन के बाहरी वृत्तीय भाग पर 1956 में निर्मित दो नई मंजिलों से सेंट्रल हॉल का गुंबद छिप गया है और इससे मूल भवन के अग्रभाग का परिदृश्य बदल गया। इसके अलावा, जाली की खिड़कियों को कवर करने से संसद के दोनों सदनों के कक्ष में प्राकृतिक प्रकाश कम हो गया। इसीलिए यह अधिक दबाव और अतिउपयोग के संकेत देने के साथ ही स्थान, सुविधाओं और प्रौद्योगिकी जैसे मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

पानी की आपूर्ति लाइनों, सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो

सिस्टम जैसी सेवाओं, जो मूल रूप से नियोजित नहीं थी, को उपलब्ध करवाए जाने से आई सीलन से भवन का समग्र सौंदर्य विकृत हो गया। इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि भवन को वर्तमान अग्नि मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं की गयी। पुराने संसद भवन में, संचार अवसंरचना और प्रौद्योगिकी पुरातन कालीन है।

वर्तमान संसद भवन तब बनाया गया था, जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र-।। में थी, वर्तमान में यह भूकंपीय क्षेत्र-IV में है। कार्यक्षेत्र की बढ़ती मांग के साथ, आंतरिक सेवा गलियारों को कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप खराब गुणवत्ता वाले और संकीर्ण कार्यस्थल बने। स्थान की लगातार बढ़ती हुई मांग को समायोजित करने के लिए, मौजूदा कार्यक्षेत्र के भीतर उप-विभाजन बनाए गए, जिससे कार्यालय में भीड़भाड़ हो गई। ऐसे अनेक कारण होने के कारण नए संसद भवन की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। नए संसद भवन के निर्माण के बाद ऐसी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल चुकी है और यह नया भवन भारत की जनता की आकांछाओं को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

विवादास्पद कानून ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों को असीमित अधिकार दिए थे और आपातकाल के दौरान (1975-1977) इसमें कई संशोधन करके इसे राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के साथ ही इंदिरा सरकार की वक्रदृष्टि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर थी, जिसकी संगठन शक्ति से इंदिरा सरकार सबसे ज्यादा डरी हुई थी। संघ के विरुद्ध प्रचार करने के लिए इंदिरा सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। 14 जुलाई

1975 को संघ सहित 25 संगठनों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया और तत्कालीन संघ प्रमुख बालासाहब देवरस को बंदी बना लिया गया। देश के सभी राज्यों में संघ कार्यालयों को पुलिस ने सील कर दिया और संघ कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी तेजी से की जाने लगी।

ऐसी स्थिति में इंदिरा सरकार के विरुद्ध अभाविप ने विरोध का झंडा उठाया। अभाविप ने पूरे देश में विरोध के विभिन्न प्रयोगात्मक तरीके अपनाए, जिनमें से एक प्रयोग यह भी था कि महात्मा गांधी के चित्र एवं उनके ही वाक्य- असत्य, अन्याय एवं दमन के झुकना कायरता है- जैसे नारों वाले स्टीकर एवं पोस्टर को प्रकाशित एवं प्रसारित करना। अभाविप के कार्यकर्ता जहां-जहां इन पोस्टरों को बांटते, चिपकाते-उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी, लेकिन न्यायालय ने कार्यकर्ताओं को निर्दोष घोषित करके रिहा कर दिया था।

सत्ता के लिए इंदिरा सरकार ने आपातकाल के रूप में देश थोपी गयी क्रूर तानाशाही के विरुद्ध देशव्यापी जनांदोलन में अभाविप की व्यापक भूमिका और छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के दायित्व का विचार करने के लिए एक भूमिगत अखिल भारतीय बैठक अहमदाबाद में संपन्न हुई। इस बैठक में अभाविप की गतिविधियों को खुले एवं भूमिगत दोनों की रूपों में संचालित करने का निर्णय लिया गया। 14 नवम्बर 1975 से लोक संघर्ष समिति द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी। सम्पूर्ण देश में बड़ी संख्या में अभाविप के कार्यकर्ताओं ने लोक संघर्ष समिति के सदस्य के नाते सत्याग्रह में कठिन मोर्चा पर अग्रिम पक्ति में रह कर संघर्ष किया।

आपातकाल के दौरान पूरे देश में अभाविप के 4,500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए गए और 650 कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी मीसा जैसे काले कानून के तहत की गयी। इसके साथ ही 1,500 कार्यकर्ता डीआरआई. कानून के तहत जेल में बंद रहे और लगभग ग्यारह हजार छात्रों ने सत्याग्रह किया एवं इतनी ही संख्या में अभाविप कार्यकर्ताओं ने बड़ी सतर्कता, धैर्य एवं अत्यंत साहसपूर्ण कार्यों एवं गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपना विरोध प्रकट किया।

इंदिरा गांधी ने देश को 21 माह तक आपातकाल में बंधक बनाकर जो भी, जैसे भी और जितने भी अत्याचार करने थे, वह सब किए। राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद करके प्रताड़ित किया गया। और फिर 21 मार्च 1977 को लोकतंत्र की शक्ति ने आपातकालरुपी राक्षस का वध कर दिया। आपातकाल की समाप्ति से पूरा देश एक नए सूरज की किरण से जगमगा उठा। आपातकाल से लड़ने और उसे समाप्त करने में सुव्यवस्थित एवं शक्तिशाली संगठन शक्ति मनोबल ने काम किया। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अभाविप की भूमिका अतुलनीय एवं अद्भुत रही। आपातकाल के दौरान अभाविप की इकाइयां देश भर में तेजी से फैली।

आपातकाल के दौरान अभाविप ने अपनी कार्यशैली, विचार एवं प्राथमिकताओं को स्पष्ट करके जनवरी-1976 में "त्रिसूत्र- लोक शिक्षा, लोक सेवा एवं लोक संघर्ष" की घोषणा की थी। यही त्रिसूत्र आपातकाल विरोधी संघर्ष में संलग्न समूची छात्र शक्ति का मंत्र बन गया। तत्कालीन परिस्थिति अर्थात तानाशाही द्वारा लोकतंत्र के निर्लज्ज हनन के विरुद्ध जन-सामान्य विशेष रूप से छात्र-युवा शक्ति को शिक्षित करना, स्थिति की गंभीरता एवं उससे उत्पन्न चुनौतियों से परिचित कराना ही "लोकशिक्षा" कहलाया। इसी प्रकार "लोक सेवा" का अर्थ सेवा एवं विविध रचनात्मक कार्यों द्वारा समाज से जीवंत संपर्क सम्बन्ध विकसित करना और छात्रों को सामाजिक सरोकार से जोड़ना रहा। आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र एवं संविधान को बंधक बनाने वाली इंदिरा सरकार के विरुद्ध प्रबल जन-आंदोलन को संगठित करना और विरोध के लिए लोकतान्त्रिक ढंग से हर संभव प्रयास करना "लोक संघर्ष" था। इस प्रकार देखें तो आपातकाल में अभाविप ने अपनी भूमिका का पूर्ण रूप से निर्वहन किया।

आपातकाल के 48 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 48 वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष में स्वदेशी संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उसे राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया गया है। स्वदेशी संसद भवन के ठीक पीछे पुराना संसद भवन भी मौजूद रहेगा। पुराना संसद भवन पूर्ण रूप से नष्ट होने तक मूक साक्षी रहेगा कि किस प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र एवं संविधान को बंधक बनाकर देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया था। ■

(सन्दर्भ : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐतिहासिक जीवन-गाथा -ध्येय यात्रा, खंड-एक)

शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलाव से वामपंथी खेमा सकते में

एनसीईआरटी की पुस्तकों से नाम हटाने की मांग को शिक्षाविदों ने बौद्धिक अहंकार बताया

देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत बदलाव की जारी प्रक्रिया का वामपंथी एवं उनके सहयोगियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों में किए जा रहे बदलाव के विरोध में कई शिक्षाविदों ने परिषद की पाठ्यपुस्तकों से अपना नाम हटाने की मांग की है। इन शिक्षाविदों ने दावा किया है कि पुस्तकों में किए जा रहे बदलाव से उनके सामूहिक रचनात्मक प्रयास खतरे में आ गए हैं। उधर इस मसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीईआरटी ने कहा कि पाठ्यपुस्तक से संबद्ध रहे किसी के भी द्वारा नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि विद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकें किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और समझ के आधार पर विकसित की जाती हैं और किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत लेखन संबंधी दावा नहीं किया जाता।

परिषद के निदेशक दिनेश सकलानी को लिखे गए पत्र में इन शिक्षाविदों ने दावा किया है कि पाठ्यपुस्तकों को विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराओं से जुड़े राजनीतिक विज्ञान विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा और सहयोग के बाद तैयार किया गया था। इसका मूल उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, संवैधानिक ढांचे, लोकतंत्र के कामकाज एवं भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण आयामों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ वैश्विक घटनाक्रम और राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक आयामों को जोड़ना भी था। लेकिन मूल पुस्तकों में कई व्यापक संशोधन किये गए हैं और इन्हें अलग तरीके की किताब बना दिया गया है। ऐसे में हमारे लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि इन्हें हमने तैयार किया और इनसे हमारा नाम जुड़े। हमारा अब मानना है कि यह सामूहिक रचनात्मक प्रयास खतरे में है।

पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में प्रताप भानू मेहता, राजीव भर्गव, प्रोफेसर नीरजा गोपाल जयाल, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, विपुल मुद्गल, के. सी. सूरी, पीटर रोनाल्ड डीसूजा, कांति प्रसाद वाजपेयी भी शामिल हैं। इससे पहले राजनीतिक विज्ञान विशेषज्ञ सुहास पालसीकर और योगेन्द्र यादव ने राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों से मुख्य सलाहकार के रूप में उनका नाम हटाने की मांग की थी। परिषद को लिखे गए एक पत्र में सुहास पालसीकर और योगेन्द्र यादव ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों से मुख्य सलाहकार के रूप में उनका नाम हटा दिया जाए। दोनों ने दावा किया था कि पाठ्य पुस्तकों को युक्ति संगत बनाने की कवायद में इन्हें विकृत कर दिया गया है और अकादमिक रूप से बेकार बना दिया गया है। जो पाठ्यपुस्तकें पहले उनके लिए गर्व का विषय हुआ करती थीं, वे अब उनके लिए शर्मिंदगी का विषय बन गयी हैं।

उधर इस मसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीईआरटी ने कहा कि पाठ्यपुस्तक से संबद्ध रहे किसी के भी द्वारा नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि विद्यालय स्तर पर पाठ्यपुस्तकें किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और समझ के आधार पर विकसित की जाती हैं और किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत लेखन संबंधी दावा नहीं किया जाता। एनसीईआरटी का समर्थन करते हुए कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, एनआईटी के निदेशकों और आईआईएम

के अध्यक्षों सहित अनेक शिक्षाविदों ने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के विवाद पर नाम को वापस लेने को अहंकारी और बुद्धिजीवी लोगों का तमाशा करार दिया है। इस शिक्षाविदों का मानना है कि विरोध करने वाले एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के अपडेशन को बाधित करना चाहते है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. संतश्री धूलिपुदी पंडित द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया कि गलत सूचनाओं, अफवाहों और झूठे आरोपों के माध्यम से वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के कार्यान्वयन को पटरी से उतारना चाहते हैं और एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अपडेशन को बाधित करना चाहते हैं। पिछले तीन माह के दौरान एनसीईआरटी जैसे एक प्रमुख सार्वजनिक संस्थान को बदनाम करने और पाठ्यक्रम बदलाव करने के लिए बहुत आवश्यक प्रक्रिया को बाधित करने के जानबूझकर प्रयास किए गए हैं। बयान में कहा गया कि नाम वापसी का तमाशा सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए है। ऐसा लगता है कि वे भूल गए हैं कि पाठ्यपुस्तकें सामूहिक बौद्धिक जुड़ाव और कठोर प्रयासों का परिणाम हैं।

पाठ्यपुस्तकों में बदलावों की व्याख्या करते हुए बयान में कहा गया कि जिन विद्वानों ने पाठ्यपुस्तक में बदलावों का सुझाव दिया है, उन्होंने ज्ञान के मौजूदा क्षेत्र में किसी भी तरह के ज्ञान के टूटने का सुझाव नहीं दिया है, बल्कि समकालीन ज्ञान की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री को तर्कसंगत बनाया है। छात्रों के लिए "अस्वीकार्य" या "वांछनीय" क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षाविदों ने कहा कि हर नई पीढ़ी को मौजूदा ज्ञान आधार में कुछ जोड़ने या हटाने का अधिकार है। पाठ्यपुस्तकों का अंतिम बदलाव 2006 में किया गया था और पाठ्यक्रम तय करने के लिए विद्वानों के चयन की प्रक्रिया "पूरी तरह से उदार, लोकतांत्रिक और मानवतावादी" थी। साथ ही चयन प्रक्रिया पिछली समितियों की तुलना में कहीं अधिक "पारदर्शी और नैतिक रूप से उचित" थी। एनसीईआरटी के निदेशक ने स्पष्ट किया था कि उच्च स्तर के मानकों को बनाए रखने के लिए एक कठोर प्रक्रिया का पालन किया गया था।

शिक्षाविदों ने लंबे समय से स्कूल पाठ्यक्रम के बदलाव की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत मंल स्कूल पाठ्यक्रम को लगभग दो दशकों से बदलाव नहीं किया गया है और पाठ्यपुस्तकों का अंतिम बदलाव 2006 में किया गया था। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव का विरोध करने वालों पर पलटवार करते हुए शिक्षाविदों ने इसे उनका "बौद्धिक अहंकार" बताया है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में वह देश भर में करोड़ों बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। जबकि छात्र नयी पाठ्यपुस्तकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह शिक्षाविद लगातार बाधाएं पैदा कर पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार रहे हैं।

पाठ्यपुस्तकों में होने वाले बदलाव पर जारी विवाद को यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने भी अनुचित बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी ने अपनी कई किताबों में संशोधन किया था, जिसके बाद कई शिक्षाविदों ने इसका विरोध जताते हुए एनसीईआरटी की किताबों से अपना नाम सलाहकार के तौर पर हटाने की भी मांग की थी। लेकिन यह विवाद बेवजह खड़ा किया जा रहा है। शिक्षाविदों की ओर से एनसीईआरटी पर किया गया हमला अनुचित है। किताबों में संशोधन पहली बार नहीं किया गया हैं, बल्कि समय-समय पर पहले भी किताबों में संशोधन होता आया है और एनसीईआरटी की ओर से किताबों का रेशनालाइजेशन किया जाना पूरी तरह से उचित है। एनसीईआरटी ने पुष्टि की है कि वह हाल ही में जारी हुए नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के आधार पर किताबों का नया सेट तैयार कर रहा है। वर्तमान में जो संशोधन किए गए हैं, वह अस्थायी हैं और यह संशोधन अकादमिक भार कम करने के लिए किये गए हैं। ऐसे में इन शिक्षाविदों की ओर से बदलाव पर विवाद खड़ा करना बिलकुल भी उचित नहीं है। इसके पीछे कोई और ही वजह लगती है। ■

(राष्ट्रीय छात्र शक्ति टीम)

The paradox of subverting democracy to establish "democracy"

| K N Pandita |

Despite many court cases pending against him, including the multi-crore National Herald, Rahul Gandhi was allowed to travel abroad without imposing genuine restrictions on him. Despite violating the rules, he was allowed to travel abroad.

The government emphatically says that all citizens are equal before the law. But Rahul Gandhi has not been treated under the law of the land. It means that the government concedes that Rahul is above the law, and has to be given a treatment different from ordinary citizens of India. What could be the reason for that? First, he is descended from a historic family that has a long history of service to the nation first as freedom fighters and next as administrators. In addition to it, the house has made two major sacrifices in the shape of the assassination of its two prime ministers.

This is a fairly strong claim based on which Rahul Gandhi can ask and get concessions. But the point is that his father and grandmother died protecting the interests of the country. They made the sacrifice of their lives to protect India's sovereignty and solidarity, to protect Indian civilization and democratic traditions as they embodied all that India boasts about. They are martyrs.

These and other martyrs would find peace in their souls if their scion could understand the greatness of Indian civilization and its values and contribute to the golden fund of her history. The foremost of all the good things which his ancestors upheld at the cost of their lives was the democratic system of India, something which Rahul Gandhi has been trying to demolish.

At least five states of India are ruled by Congress, the party to which Rahul belongs, and still he says that democracy is dead in India. In his speeches, he very confidently says that his party will emerge victorious in the 2024 parliamentary elections in India. This is a contradiction in terms. If in his opinion democracy is dead, how does he expect his party to emerge victorious in the impending election? It simply means he wants to degrade and disparage the roots of democracy that were laboriously nourished by his ancestors. To them, he is a pariah. One who disgraces and undermines the contribution of his ancestors does not enjoy any respect from the Indian nation.

The worst is that he chooses to defame and denigrate his native country not only on its soil but also in foreign countries while on a visit. In London, he said that he was not allowed to speak in the parliament and that his microphone was blocked. But he forgets that on his behest other parties on the opposition benches disrupted scores of Lok Sabha and Rajya Sabha sessions umpteenth times by creating a ruckus in the house or proceeding on strikes and boycotts. He was instrumental in dissuading the opposition parties to reject the Prime Minister's invitation to attend the function of the opening ceremony of the new building for the Indian parliament. Imagine the level of hatred Rahul Gandhi carries in his heart

against Prime Minister Modi that he does not even have an iota of respect for the nation that joyously celebrated a great occasion of throwing open a new parliament house with all ultra-modern facilities and accessories.

In London, he lamented the "death of Indian democracy" and in the USA he accepted the hospitality of at least nine Muslim organizations with members and functionaries connected closely with terrorist groups in Pakistan. Among his audience at various places in the US, mostly anti-India American Muslims were the participants. The American Muslims are the Muslims from Pakistan and Kashmir who have earned American citizenship and have been taking an active part in collecting huge funds for transfer to such terrorist organizations in Kashmir as are training terrorists for operations in the Indian part of Kashmir.

Compare the role of Rahul's grandmother Indira Gandhi and his own vis-a-vis Pakistan and you will find that Rahul is the antithesis of Indira Gandhi. He should have read the biography of Indira Gandhi and understood where our national interests lie.

Rahul Gandhi usually never discloses any information about his trips abroad; when and where he goes, whom he meets, what transpires between him and his hosts or the itinerary of his travels abroad. He said he was going on a pilgrimage to Mansarovar but he crossed over and went to China and had secret meetings with the Chinese intelligence sleuths and leaders. As an outstanding leader of an important political party of which he was the president also for some time, it behoves his dignity to tell his nation where he goes and whom he meets and what transpires.

For example, news published in an American newspaper with a Washington date line says that Rahul had met with some officials at the State Department. At least the name of one Mir Lu, the Assistant Secretary of State was mentioned by the paper with whom Rahul met. We fully know the antecedents of this official. However, meeting with officials, whether on his request or the invitation by the official, is not any serious matter but the dignity and decency are that he should tweet about it and tell his countrymen, or at least his party men, about his activities. He cannot hide it because the nation needs to be informed of what its leaders are doing. The paper has further informed that Rahul had gone to the White House also. Even the White House did not make any mention of it which is very strange and suspicion-evoking.

We know that the US pretends it is a democratic country and that it cannot stop people from expressing their views. But the US has to understand that it has close relations with India in crucial fields and sensitive matters and that it should politely caution anybody speaking in a manner that would harm good relations between the two countries. It did not. Democrats have a history of having no friendly impression of India and the Biden administration is not different.

Modi government has given full freedom to Rahul Gandhi in using all the filthy language he commands to denigrate the Prime Minister because he cannot digest sitting on the opposition benches. But now is the time that PM Modi should shun all hesitation and cancel his impending visit to Washington arguing that an administration that turns away from stopping his detractors from spreading a false propaganda to undermine his visit must understand the norms of protocol and its moral responsibility. What Rahul wants to do is to destroy Indian democracy and impose a prototype of Mussolini's regime. ■

अभाविप की चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक पुणे में संपन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक का आयोजन गत 25-28 मई को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के महर्षि कर्वे स्त्री-शिक्षण संस्था में हुआ। बैठक में सभी राज्यों से आए साढ़े तीन सौ अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, जिसमें मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आगामी 9 जुलाई को अभाविप अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। जानकारी हो कि अभाविप ने अपने कार्यों का प्रारम्भ 1948 में किया था, जिसका विधिवत पंजीयन 9 जुलाई 1949 को हुआ।

पुणे में संपन्न कार्यकारी परिषद बैठक में अभाविप ध्येय यात्रा के 75वें वर्ष के सुअवसर पर विद्यार्थियों एवं युवाओं से जुड़े विषयों को वृहद स्तर ले जाने की कार्ययोजना पर चर्चा की गयी। साथ ही अभाविप 75 विषय पर पुस्तक लेखन के सम्बन्ध पर भी विचार किया गया। बैठक का शुभारंभ गत 25 मई की को अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल एवं संगठन मंत्री आशीष चौहान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बैठक के आरंभ में सभी प्रतिनिधियों का ढोल बजाकर, पुष्प वर्षा द्वारा तथा स्थानीय पारंपरिक टोपी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया।

कार्यकारी परिषद के प्रास्ताविक सह उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही ने कहा कि देश के स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में पुणे राष्ट्रीय उद्घोष का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। पुणे की भूमि ने, न केवल भारत की गौरवाशाली इतिहास को जोड़ने का काम किया, बल्कि भारत की संस्कृति को भी समृद्ध किया है। यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का कालखंड तो है ही, साथ-ही-साथ अभाविप की ध्येय यात्रा का 75वां वर्ष भी है। अभाविप की 75 वर्ष की यशस्विता के पीछे एक वैचारिक अधिष्ठान काम कर रहा है। अभाविप ने अपनी इस यात्रा में भारत की शिक्षा को भारत की मिट्टी के साथ के साथ जोड़ने के लिए संघर्ष किया है। भारत की शिक्षा को भारतीय संस्कृति और संस्कारों के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुनहरा अवसर लेकर

आई है। पुणे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक से अभाविप कार्यकर्ताओं को नई दिशा और नया संकल्प मिलेगा।

जानकारी हो कि अभाविप की कार्यकारी परिषद बैठक न केवल समीक्षा विषय होती है, बल्कि इस बैठक में अभाविप अपने आगामी दिशा भी तय करती है। चार दिन तक चली कार्यकारी परिषद में यह निर्णय किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अभाविप के आयाम, कार्य, गतिविधियों द्वारा युवाओं के नेतृत्व में कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण, सेवा, तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में युवा नेतृत्व के माध्यम से भारतीयता केन्द्रित विचार द्वारा सकारात्मक परिवर्तन के लिए विभिन्न अभियान शुरू किए जाएंगे। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य, शिक्षा में भारतीयता केंद्रित विचार की स्थापना, पाठ्यक्रमों का वर्तमान की आवश्यकताओं के

दिल्ली में होगा अभाविप का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का 69 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। यह निर्णय पुणे में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में लिया गया। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 12 वर्ष बाद होगा। इससे पहले 2011 में दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अभाविप के 69 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन आगामी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक होगा और अधिवेशन में देश भर के हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे।

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा का आयोजन नवंबर में

राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित करने के उद्देश्य से 1966 से चल रहे अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन यात्रा आयोजन आगामी 5 नवंबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। अबकी बार शेष भारत के छात्र पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगें और वहां की संस्कृति, परंपरा, खान-पान, रहन-सहन से परिचित होंगे। जानकारी हो कि पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने, उनकी संस्कृति, परंपरा को भारतीय युवाओं को परिचित कराने तथा पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को शेष भारत की संस्कृति, परंपरा से परिचित कराने एवं एकात्मता स्थापित करने के लिए हर वर्ष अंतर-राज्य छात्र जीवन दर्शन यानी सील के द्वारा राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में छात्र/युवा किसी होटल या सराय में ठहरने के बदले परिवार में ठहरते हैं। इस दौरान उनका परिवार के साथ ऐसा आत्मीय संबंध बन जाता है कि वह जीवन भर के लिए उनसे जुड़ जाते हैं।

शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगी अभाविप

छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के गौरवशाली अवसर को उमंगपूर्ण तरीके से मनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) देशभर के शैक्षणिक परिसरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। राज्याभिषेक की वर्षगाठ के अवसर पर विश्वविद्यालय परिषर में भाषण, नाटक एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को उनके जीवन चरित्र से परिचित कराया जाएगा। साथ ही अभाविप विद्यार्थियों के मध्य 'आनंदमय सार्थक छात्र जीवन अभियान' अभियान के अंतर्गत विविध रचनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाएगी, जिससे विद्यार्थियों का परिसर जीवन तनावमुक्त होकर आनंदमय हो सके।

जानकारी हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 349 वर्ष पहले 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। 1674 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। रायगढ़ में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी।

अनुरूप निर्माण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं विद्यार्थियों की क्रियान्वयन में सहभागिता, स्वावलंबी भारत आदि विषयों पर सार्थक चर्चा होने के साथ ही आगामी कार्ययोजना निर्धारित की गयी।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में कुल चार प्रस्ताव पारित किए गए। यह चार प्रस्ताव 'प्रदेश सरकारें व विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता पर दें ध्यान', 'आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन का केन्द्र बने परिसर', 'भारत विरोधी वैश्विक षड्यंत्र को परास्त करें युवा', 'स्व आधारित व्यवस्था निर्माण हेतु समाज हो अग्रसर' शीर्षक केन्द्रित हैं। इन प्रस्तावों पर अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में पारित चारों प्रस्तावों में उठाए गए विषयों पर अभाविप की सभी इकाईयां कार्य करेंगी।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के अनुसार अभाविप की यात्रा छात्र हित व समाज हित के स्वर्णिम अध्यायों को समेटे हुए है। वर्तमान में देश में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है। अभाविप विद्यार्थियों की शिक्षा, स्वरोज़गार, राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार, शुल्क से जुड़े विषयों पर प्रमुखता से कार्य करने के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में युवा नेतृत्व में सकारात्मक दिशा में कार्य करती रहेगी। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित प्रस्तावों में उल्लेखित विभिन्न बिंदुओं को संबंधित स्थानों पर उठाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों व शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों को इस दिशा में सोचना होगा कि विद्यार्थियों में व्यावहारिक समझ विकसित कर उन्हें स्टार्टअप शुरू करने तथा रोजगार सृजक की भूमिका के लिए तैयार किया जाए।

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने बैठक के दौरान प्रांतशः (प्रांतवार) संगठनात्मक कार्य, गतिविधि, सदस्यता, आंदोलन, कार्यक्रम इत्यादि की समीक्षा की। उन्होंने इस निमित्त प्रांतवार आंकड़े भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद अपने 75 वें वर्ष में प्रवेश कर रही है ऐसे में हमें अपने कार्यों को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश भर का कोई भी परिसर परिषद के कार्यों से अछूता न हो। वर्ष भर विद्यार्थी परिषद के कार्यों की श्रृंखला चलते रहती है। उन्होंने अपने विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से परिसर के सभी छात्रों को परिषद से जोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने विद्यार्थी परिषद के स्वरूप, कार्यपद्धति पर चर्चा करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्य एवं उद्देश्य से

अभाविप आयाम मेडिविजन प्रारम्भ करेगी निरामय ग्रामीण स्वास्थ्य इंटर्नशिप

चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले अभाविप प्रकल्प मेडिविजन के द्वारा निरामय ग्रामीण स्वास्थ्य इंटर्नशिप प्रारम्भ की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक इंटर्नशिप के पोस्टर का विमोचन अभाविप अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, सह-संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण, मंत्री वीरेन्द्र सोलंकी एवं मेडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक अभिनंदन बोखरिया ने किया। मेडिविजन संयोजक अभिनंदन बोखरिया ने निरामय ग्रामीण स्वास्थ्य इंटर्नशिप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच लुप्त हुई कड़ी को चिकित्सीय रूप से जोड़ना है। इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यार्थियों में समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। यह इंटर्नशिप चिकित्सा से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर रहे छात्र एमडी, एमएस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीडीएस के लिए होगी। इंटर्नशिप के माध्यम से छात्र जहां ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे, वहीं गांव में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा। छात्र ग्रामीणों के बीच विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का काम भी करेंगे।

थिंक इंडिया की रिपोर्ट का विमोचन

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के तीसरे दिन थिंक इंडिया द्वारा गत जनवरी को दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में आयोजित छठे सिम्पोजियम लैंडमार्क जममेंट के रिपोर्ट से संबंधित ब्रोशर का विमोचन, अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, थिंक इंडिया प्रमुख सुमित पांडेय, संयोजक प्रतीक सुथार एवं सह संयोजक आकांक्षा वराडे द्वारा किया गया। यह रिपोर्ट वर्ष 2022 में न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों पर केन्द्रित थिंक इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी पर केन्द्रित है। जानकारी हो कि थिंक इंडिया अभाविप का अखिल भारतीय शिक्षण कार्य है, जो देश के प्रीमियर शैक्षिक संस्थानों आईआईटी, एनआईटी, एनएलयू व अन्य संस्थानों के छात्रों के बीच कार्य करता है।

थिंक इंडिया संयोजक प्रतीक सुथार के अनुसार जनवरी 2023 में वर्ष 2022 में न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों पर 'केन्द्रित लैंडमार्क जजमेंट-2022' पर छठी राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसके समापन सत्र में माननीय न्यायमूर्ति सी. डी. सिंह और भारत के सहायक सॉलिसिटर-जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रमजीत बनर्जी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी को चार सत्रों में विभाजित किया गया था। पहले सत्र में जनहित अभियान बनाम भारत संघ-ईडब्ल्यूएस निर्णय पर था। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एस. गुरुकृष्ण कुमार मौजूद थे। दूसरा सत्र ऐशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य के मामले पर था। इस सत्र के वक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और वरिष्ठ अधिवक्ता रचना रेड्डी शामिल रहे। तीसरा सत्र आरआईटी फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले पर था। इस सत्र की अध्यक्षता जे. साईं दीपक ने की। चौथे और अंतिम सत्र में प्रसिद्ध पीएमएलए निर्णय अर्थात विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ पर चर्चा हुई। इस सत्र के वक्ताओं में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी शामिल थे।

संवेदन प्रकल्प विवरणिका का विमोचन

सेवार्थ विद्यार्थी गुजरात प्रांत द्वारा चलाए जा रहे 'संवेदन' प्रकल्प की विवरणिका का विमोचन अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, सेवार्थ विद्यार्थी की राष्ट्रीय संयोजक मुस्कान आनंद, सह संयोजक भवानी शंकर एवं अभाविप गुजरात प्रांत मंत्री युति प्रदीप द्वारा किया गया। 'संवेदन' प्रकल्प 'शिक्षा के साथ सुरक्षित वन, सेवार्थ बने विद्यार्थी मन' सेवार्थ विद्यार्थी गुजरात प्रांत द्वारा 2015 से चलाया जा रहा है। इस प्रकल्प के अंतर्गत विभिन्न परिसरों में विद्यार्थियों से रिक्त पेज एकत्रित करने के पश्चात पुनर्प्रयोग से नई नोटबुक बनाकर वंचित क्षेत्र के विद्यार्थियों को वितरित की जाती हैं।

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2023 पर केन्द्रित स्मारिका 'पूर्वोदय' का विमोचन

पुणे में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में अभाविप प्रकल्प अंतर-राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकातम्कता यात्रा-2023 की स्मारिका पूर्वोदय का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री राकेश दास, अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन के अध्यक्ष अतुल कुलकर्णी, सचिव गीतेश सामंत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री कमल नयन एवं यात्रा के संयोजक अनूप कुमार सह-संयोजिका डारीलीन तांग द्वारा किया गया।

पूर्वोदय स्मारिका राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा पर केन्द्रित है। स्मारिका में देशभर में की गयी यात्राओं, भारत की सांस्कृतिक एकात्मता, प्रतिनिधियों के अनुभव को रेखांकित किया गया। स्मारिका को सील यात्रा के मनोहर तस्वीरों से सुसज्जित किया गया है। जानकारी हो कि सील अभाविप का एक प्रकल्प है, जिसकी स्थापना भारत-चीन युद्ध के बाद पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने एवं उसके बीच एकात्मता स्थापित स्थापित करने के लिए उद्देश्य से 1966 में की गई थी। 1966 से लगातार हर वर्ष एकात्मता यात्रा का आयोजन किया जाता है।

परिचित कराया।

25 मई से होकर 28 मई 2023 तक हुई अभाविप की चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में वर्ष भर के कार्यक्रमों, अभियानों की रूपरेखा तय की गई। अभाविप ने बैठक में शैक्षणिक परिसरों को तनावमुक्त बनाने के लिए सरकार तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन से शीघ्र कदम उठाए जाने की मांग की है। अभाविप ने इस वर्ष देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 'आनंदमय सार्थक छात्र जीवन अभियान' शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां, कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाएगा। आगामी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रांत योजना अनुसार अभाविप अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन भी करेगी। अभाविप की आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक का आयोजन 5 से 6 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होगा। आयोजित होगी।

पुणे में हुई परिषद बैठक में भारत को स्वावलंबी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से स्वावलंबी टोली बनाने का भी विचार सामने आया है। साथ ही 75 स्थानों पर रोजगार सृजन केन्द्र खोलने के विषय पर भी विचार किया गया। अभाविप ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आगामी 21 अगस्त यानी विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर उद्यमिता सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय भी लिया है। इसी के साथ रानी दुर्गावती के पराक्रम एवं शौर्य को जन-जन को पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 5 अक्टूबर को देशभर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकात्मता को स्थापित करने के लिए 1966 से जारी अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन यात्रा आयोजन आगामी 5 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। इस बार शेष भारत के छात्र पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगें और वहां की संस्कृति, परंपरा, खान-पान, रहन-सहन से परिचित होंगे।

बैठक में प्रांत स्तर पर शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर कार्यशाला आयोजन करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य पर सात दिन तक विविध स्वरूप में कार्यक्रम का आयोजन के साथ ही 15 अगस्त को एक गांव-एक तिंरगा अभियान का आयोजन भी किया जाएगा। ■

नागरिक अभिनंदन समारोह में अभाविप के कार्यों की सराहना

अभाविप राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के तीसरे दिन 'नागरिक अभिनंदन समारोह' का आयोजन किया गया। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय थलसेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम. एम. नरवणे तथा महाराष्ट्र सरकार के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में अहम योगदान दे रहा है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आता है तो उसमें कई कारक शामिल होते हैं और राष्ट्र को सुरक्षित रखना केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा सेना के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है, इसमें कई चीजें शामिल हैं। कई खतरे हैं। बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे भी हैं और ऐसे खतरे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल हैं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल साइबर सुरक्षा आदि। यह सभी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा हैं और हर कोई जो इससे जुड़ा हुआ है, उन्हें सुरक्षित करने में योगदान देता है। इसलिए देश को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी की है।

पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा कि हमें एक-दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। अनेकता में एकता का नारा, अनेकता में शक्ति का नारा भी बनना चाहिए। जब हम अनेकता को शक्ति मानेंगे तो और आगे बढ़ पाएंगे। वह सभी से अनुरोध करते हैं

कि अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के साथ एक और भाषा सीखनी चाहिए। एक और भाषा सीखने से अनेकता में शक्ति को बल मिलेगा।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो हमारे विद्यार्थियों को एक नई दिशा देता है। अभाविप के कश्मीर आंदोलन ने उनके जीवन को नया मोड़ दिया। जीवन में संघर्ष और दृढ़ता के साथ आंदोलन उन्होंने अभाविप से सीखा। साथ में उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास विद्यार्थी परिषद के कारण हो पाया। अभाविप एक ऐसा फोरम है, जहां सामान्य से सामान्य युवा अभाविप की कार्यपद्धति द्वारा टीम वर्किंग सीखता है, उसमें नेतृत्व गुण का विकास होता है और वह क्षमतावान बनता है। स्वतंत्रता के बाद मैकाले की मानसिकता वालों ने भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबाने का प्रयास किया और भारत के वास्तविक इतिहास से हमें दूर रखा गया। भारत की सभ्यता सबसे प्राचीन है। इसलिए देशवासियों के सामने सही इतिहास सामने लाना होगा और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है।

उन्होंने कहा कि आज हम जिस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वह भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से ही मौजूद रही है और इसी सस्टेनेबिलिटी ने भारतीय सभ्यता को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को विकसित करने में सहायक हो सकता है। भारत में एक विचारधारा ऐसी है जो युवाओं की मानसिकता में वायरस छोड़ने का कार्य कर रही। बंदूक से लड़ने वाले माओवादी कम हुए हैं, लेकिन वैचारिक माओवादी हमारे शैक्षणिक परिसरों में मौजूद हैं। उनके विरूद्ध एकजुट होना होगा। भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो समाज और राष्ट्र का विचार करने वाले युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही ने कहा कि मैकाले की शिक्षा का उद्देश्य भारत की मूल चेतना पर प्रहार करना था। मैकाले को मालूम था कि इस राष्ट्र की चेतना पर प्रहार किए बिना यहां पर अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में शिक्षा नहीं थी, उस समय भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। मैकाले ने योजनाबद्ध तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति को खत्म करने का प्रयास किए।भारत में शिक्षा जीवन एवं राष्ट्र केंद्रित थी। अभाविप ने अपने 75 वर्षों की ध्येय यात्रा में भारत की शिक्षा परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभाविप की पूरी यात्रा रचनात्मकता की यात्रा है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि पुणे प्राचीन संस्कृति से लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की गाथा समेटे है। पुणे भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद जो संकल्प अधूरे रह गए, उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति का नाम विद्यार्थी परिषद है। विद्यार्थी परिषद युवाओं की वास्तविक आवाज है, अभाविप के कार्यकर्ताओं ने अपने विभिन्न कार्यों से समाज में सकारात्मक संदेश दिया है और विविध क्षेत्रों में युवाओं ने समाज की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए प्रेरणादायक काम किया है।

भारत फोर्ज के चेयरमैन सह नागरिक अभिनंदन समारोह के स्वागत समिति अध्यक्ष बाबा साहेब कल्याणी ने कहा कि भारत में शिक्षा के भविष्य को तय करने के लिए अभाविप का यह बैठक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनगिनत युवाओं में देशभक्ति के भावना को विकसित करने का कार्य किया है, जिसकी वह सराहना करते हैं। कोरोना काल के दौरान भारत ने स्वयं का कोरोना वैक्सीन का

निर्माण किया जो प्रशंसनीय रहा और वैज्ञानिकों ने ऐसा करके भारत को गौरवान्वित किया। भारत के नवाचार, नवोन्मेशी पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की जल्द ही भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक दौरान'नागरिक अभिनंदन समारोह' किया गया। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे तथा महाराष्ट्र सरकार के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, नागरिक अभिनंदन समारोह की स्वागत समिति के अध्यक्ष बाबासाहेब कल्याणी, स्वागत समिति सचिव बागेश्री मंठाळकर, अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री अंकिता पवार, अभाविप पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के प्रांत अध्यक्ष प्रा. निर्भयकुमार विसपुते तथा प्रांत मंत्री अनिल ठोंबरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुणे के गणमान्य नागरिकों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में अभाविप की स्मारिका का विमोचन किया गया और अंत में 'जाणता राजा' नाटक का मंचन हुआ। ■

केन्द्रीय कार्यसमिति, आयाम तथा प्रांत कोषाध्यक्ष बैठक का आयोजन

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के प्रारम्भ होने से पूर्व 25 मई 2023 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केन्द्रीय कार्यसमिति, आयाम तथा प्रांत कोषाध्यक्ष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्घाटन अभाविप राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान तथा विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो. नागेश ठाकुर ने दीप प्रज्ज्वलित कर एवं मां सरस्वती तथा विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। बैठक में आयामों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आयाम-गतिविधि जैसे- थिंक इंडिया, सेवार्थ विद्यार्थी, विकासार्थ विद्यार्थी, जिज्ञासा आदि आयाम तथा राष्ट्रीय कलामंच, खेल आदि गतिविधि एवं कार्यालय आदि मिलाकर 17 बैठक संपन्न हुई। आदी से संबंधित देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अभाविप पदाधिकारियों ने कहा कि विविध क्षेत्रों में युवाओं के सकारात्मक योगदान के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न आयाम तथा गतिविधियां सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। देश के युवाओं को सकारात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए विविध प्रयास प्रारम्भ किए जा रहे हैं। रचनात्मक कार्यों से युवा विविध क्षेत्रों में बेहतर कर सकते हैं। बैठक में अभाविप के आयामों के माध्यम से तय किया गया है कि पर्यावरण, सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य किया जाएगा। ■

छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित 'जाणता राजा' नाट्य का मंचन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के दौरान आयोजित 'नागरिक अभिनंदन समारोह' में 'जाणता राजा' नाटक का मंचन हुआ। नाटक में शिवाजी के छत्रपति बनने की भव्य गाथा को दर्शाया गया। यह महानाट्य स्वर्गीय बाबा साहब पुरंदरे ने लिखा है। रिकॉर्डेड संवाद के साथ कलाकारों ने मंच पर प्रवेश किया। शानदार सजावट, भव्य लाइट शो एवं जानदार संवाद के साथ कलाकार दर्शकों को 350 साल पीछे ले गए। महानाट्य में जब शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया, ढोल, नगाड़े के संगीत और स्थल पर की गई आतिशबाजी के देख कर ऐसा लगा कि सभी शिवाजी युग में प्रवेश कर चुके हों।

छत्रपति शिवाजी महाराज के कीर्तिमान उनके शौर्य की गाथा महानाट्य के स्वरूप में देख विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता सहित उपस्थित पुणेवासी अभिभूत हो गए और समारोह स्थल जय भवानी-जय शिवाजी नारों से गूंज उठा। महानाट्य में शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को भी उजागर किया गया।

सात नदियों के पवित्र जल से शिवाजी किया गया था राज्याभिषेक

शिवाजी का 6 जून 1674 को यमुना, सिंधु, गंगा सहित सात नदियों के पवित्र जल से राज्याभिषेक किया गया था। गोदावरी, नर्मदा, कृष्ण और कावेरी के जल को शिवाजी के सिर पर डालते हुए और वैदिक राज्याभिषेक मंत्रों का जाप किया गया था। रायगढ़ में जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उन्हें छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी।

शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी, 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली थी। इसलिए उन्होंने दुनिया के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। शिवाजी महाराज ने बहुत कम आयु में ही टोरना किले पर कब्जा कर अपनी प्रतिभा और युद्धकौशल का परिचय दे दिया था और इसके बाद तो उन्होंने कई इलाकों को मुगलों से भी छीन लिया था। ■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित प्रस्ताव

शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता पर ध्यान दें प्रदेश सरकारें एवं विश्वविद्यालय प्रशासन

वर्तमान में देश में विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय श्रेणी के कुल 1113 संस्थान, 43796 महाविद्यालय तथा 11296 एकल शैक्षणिक (Stand-alone) संस्थान हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021 की रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में नामांकन 4.14 करोड़ हो गया है और पहली बार उच्च शिक्षा नामांकन में चार करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। उपर्युक्त आंकड़ें स्पष्ट करते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। वर्तमान में भारत में विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में युवा-2022' नामक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की आधी से अधिक लगभग 53 प्रतिशत जनसंख्या 29 वर्ष या उससे कम आयुवर्ग की है। देश का युवा वर्ग राष्ट्र तथा विश्व-कल्याण निमित्त स्वयं को सक्षम बना सके, इसमें शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने के उपरांत देश के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन होने की अपेक्षाएं हैं।वर्तमान में उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थियों की बड़ी संख्या राज्य विश्वविद्यालयों, उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कुल 432 निजी विश्वविद्यालय, 464 राज्य विश्वविद्यालय व इनसे सम्बंधित बड़ी संख्या में महाविद्यालय हैं। देशभर के इन सभी शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न पक्षों में वृहत स्तर पर सुधार की अत्यंत आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

देश की विभिन्न राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैए तथा राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार व उदासीनता के कारण बहुत सी व्यवस्थागत समस्याएं उत्पन्न हो गई है जैसे-आधारभूत ढांचे का भारी अभाव, शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों का रिक्त होना, विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति कम होना, शैक्षणिक सत्र में दो-ढाई वर्ष तक का विलंब, शुल्क बढ़ोत्तरी। इन समस्याओं के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में प्रश्न पत्र का लीक होना एक गंभीर समस्या है। इन समस्याओं के कारण विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा रहता है। मई, 2022 में शिमला में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में अभाविप ने राज्य सरकारों का आह्वान किया था कि वे विद्यार्थियों के हितों की चिंता करते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप बंद कर संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु आगे आएं।

राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का मत है कि -

1. राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक सभी रिक्त पदों की सूचना को सार्वजनिक करते हुए इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।
2. राज्य सरकारें शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाएं तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र के बजट आवंटन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
3. देश के राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध

महाविद्यालयों में वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप आधार-भूत ढांचे का विकास, पाठ्यक्रमों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित अद्यतनीकरण व उन्हें स्वरोजगारोन्मुखी बनाना, राज्य के विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप कम्प्यूटर आधारित शिक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को ध्यान रख अधुनातन डिजिटल प्रयोगशालाओं का विकास, सत्र नियमन आदि दिशाओं में शीघ्रता से प्रयास हों तथा महाविद्यालयों की सम्बद्धता संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

4. सभी शैक्षणिक संस्थानों को बहुविषयक शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित करने की दिशा में पहल की जाए।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के पूर्ण क्रियान्वयन की दिशा में शीघ्रता से कदम बढ़ाए जाएं जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप युवा वर्ग के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त कर सके, विश्वविद्यालय यह प्रयास करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सभी विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स गठित की जाए व इस प्रक्रिया में हितधारक के रूप में विद्यार्थियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जाए।
6. निजी विश्वविद्यालयों के नियमन हेतु राज्य सरकारें विशेष ध्यान दें तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे शिक्षा के व्यापारीकरण पर लगाम लगाने हेतु कड़े कदम उठाये जाए।
7. विश्वविद्यालयों में प्रत्येक सत्र में विद्यार्थी केन्द्रित विषयों पर विशेष कार्यकारी परिषद व कार्यकारी परिषद में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक राज्य सरकारों से तथा राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रशासकों से आह्वान करती है कि इन सुधारों की दिशा में शीघ्रता से प्रयास सुनिश्चित करें। ■

अभाविप गोरक्ष प्रांत द्वारा मऊ में छात्रा सम्मेलन का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गोरक्ष प्रांत द्वारा मऊ में छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्राओं को सशक्त बनाने का नेतृत्व कर रही हैं।

शिक्षा मंत्री ने छात्राओं से -द केरल स्टोरी-फिल्म को देखने की अपील करते हुए कहा कि यह फिल्म इसलिए देखनी चाहिए ताकि हमारी मासूम लड़कियां गलत कदम उठाना बंद कर दे। फिल्म को देखकर लड़कियां अपनी सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता, अनुशासन को बनाए रखेंगी और गलत कदम उठाने से बचाएंगी। इस अवसर पर अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी प्रताप सिंह ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। विद्यार्थी परिषद ने महिला शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मिशन साहसी नामक अभियान भी चलाया है।

उन्होंने कहा कि अभाविप गोरक्ष प्रांत द्वारा आयोजित यह छात्रा सम्मेलन समाज और संगठन में छात्राओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाएगा। सम्मेलन में अभाविप गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष प्रो. सुषमा पांडेय ने कहा कि अभाविप अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, राष्ट्रहित एवं समाजहित में कार्य कर रहा है। छात्रा सम्मेलन का आयोजन गत 15 मई को मऊ स्थित आर. एस. पैलेस में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के पहले शोभायात्रा भी निकली गई, जिसका कई स्थानों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित प्रस्ताव

आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन के केंद्र बनें परिसर

भारत की शिक्षा व्यवस्था जीवनमूल्य केंद्रित, जीवंत एवं आनंददायी थी। भारतीय शिक्षा व्यवस्था जीवन को सार्थकता प्रदान करने में सहायक थी, जिससे विद्यार्थी में संवेदनशीलता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन का भाव भी जागृत होता था। विदेशी आक्रमणों के काल में भारत की स्व-आधारित शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चोट पहुंची। अंग्रेजो द्वारा थोपी गई शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मूल स्वभाव को ही खंडित कर दिया। परिणामस्वरूप शिक्षा में पाठ्यक्रम का दबाव बढ़ता गया और परिसर नीरस होते गए। परिसरों में केवल पाठ्यक्रम पूर्ति पर जोर देते हुए मानों एक अदृश्य दौड़ में भाग लेने के उद्देश्य से शिक्षा दिए जाने के कारण विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ता गया, जिससे विद्यार्थी समाज से भी दूर होते गये। आज औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के कारण उत्पन्न इस प्रकार की विकृतियों को दूर कर आनन्दमयी एवं सार्थक विद्यार्थी जीवन के निर्माण के लक्ष्य वाली भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है। अतः अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का यह सुविचारित मत है कि-

1. बस्ते का बोझ कम करते हुए विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा सहित सहपाठ्यक्रम गतिविधियों को परिसर एवं विद्यार्थी जीवन का आवश्यक भाग बनाया जाए।
2. परिसर में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को उचित स्थान देने तथा उनके प्रदर्शन के निमित्त रचनात्मक गतिविधियों का संचालन हो व अध्ययन के साथ-साथ स्वरोजगार के साधन तैयार करते हुए विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास हों।
3. पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रक्रिया गतिविधि आधारित हों। परिसर विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सृजनशीलता, शिल्प कौशल तथा पारंपरिक कौशल के प्रकटीकरण के उचित स्थान बनें।
4. परिसर में विद्यार्थियों से स्वस्थ वातावरण में मुक्त संवाद को प्रोत्साहित किया जाये तथा विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त रखने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन हो। शरीर, मन तथा बुद्धि के सर्वांगीण विकास हेतु खेल, आध्यात्म एवं योग को भी विद्यार्थियों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए।
5. विद्यार्थियों की समस्या समाधान हेतु विशेष सत्र आयोजित किए जाने के साथ ही शिक्षकों का विद्यार्थियों से नियमित संवाद स्थापित हो 1 इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 22 जनवरी 2021 के दिशानिर्देश में उल्लिखित मार्गदर्शक- प्रशिक्षक (Mentor-Mentee)की संकल्पना को गंभीरता से लागू किया जाए।
6. विद्यार्थियों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु दैनिक जीवन में प्रकृति संरक्षण संबंधी उत्सव, त्यौहार एवं अन्य गतिविधियों का संपादन भी परिसरों में हो।
7. विद्यार्थियों में समाज के प्रति संवेदना व समरसता उत्पन्न करने हेतु उन्हें सामाजिक अनुभूति अथवा अनुभूति शिविर तथा राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी गतिविधियों में सहभाग हेतु अवसर मिले जिससे उनमें सेवा भाव जागृत हो।
8. परिसर का वातावरण विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम के संस्कार को जागृत करने वाला हो। इस निमित्त भारत माता नमन स्थल, भारत दर्शन गलियारा, राष्ट्रध्वज वंदन स्थल, युद्ध विजय स्मारक इत्यादि प्रयोग किए जाए।

इस प्रकार के उपक्रमों को परिसर गतिविधियों का हिस्सा बनाते हुए विद्यार्थियों में भारतीय जीवन मूल्यों का विकास किया जाए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद समस्त शैक्षणिक संस्थानों के प्राध्यापकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान करती है कि विद्यार्थियों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के साथ ही विद्यार्थी जीवन को आनंदमयी तथा सार्थक बनाने हेतु गंभीर प्रयास सुनिश्चित करें। ■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित प्रस्ताव

भारत विरोधी वैश्विक षड़यंत्रकारी ताकतों को परास्त करे युवा

आज समूचा विश्व भारत की जी-20 समूह की अध्यक्षता में सम्मिलित होते हुए भारतीय संस्कृति, मूल्यों एवं भारत की 'एकता की विविधता' के साथ-साथ 'वसुधैव कुटुम्बकम'के भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में उभरता हुआ भारत सकारात्मक नेतृत्व प्रदान कर रहा है और विश्व में भारत के बढ़ते सम्मान का प्रमाण अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट आतिथ्य के द्वारा भी मिलता है। आज भारत 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक नेतृत्व की भूमिका में उभरा है। इसी वर्ष भारत के कला जगत ने प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार फिल्म 'आरआरआर' के 'नाटू-नाटू' गीत तथा भारतीय संस्कृति में निहित मानव एवं प्रकृति में सहअस्तित्व के मूल भाव को प्रदर्शित करने वाले वृत्तचित्र 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' के लिए जीतकर विश्व के समक्ष इस भाव को प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक बनने की ओर अग्रसर है और भारत में वित्तीय प्रोद्योगिकी (FinTech) अपनाने की दर (87 प्रतिशत) दुनिया में सबसे अधिक है। भारत ने एक महीने में एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ (Unified Payment Interface) के माध्यम से 360 करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सबसे उच्चतम लेन-देन भी दर्ज किया है। आज हम भारतीय मुद्रा 'रुपए' से विश्व के 18 देशों में व्यापार व लेन-देन कर सकते हैं। 'सीआईआई-मैकिन्से' (CII-McKinsey) की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि उत्पादन वर्ष 2030 तक 29.28 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है और खाद्य निर्यात 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य होने की संभावना है। स्वाधीनता के 75 वर्ष के निमित्त आज भारत औपनिवेशिकता के एक और प्रतीक पुराने संसद भवन को छोड़कर स्वनिर्मित नवीन संसद भवन में प्रवेश कर रहा है। हाल ही में भारत ने जी-20 के पर्यटन समूह की बैठक जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक आयोजित कर विश्व के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर का समाज व प्रशासन प्रशंसा के पात्र हैं।

दूसरी ओर कुछ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारी ताकतें भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नेतृत्व के खिलाफ खड़ी दिखाई देतीहैं। कुछ दिन पूर्व 'बीबीसी वृत्तचित्र' द्वारा भारत विरोधी कुछ विदेशी एजेंसियों ने एक सामूहिक षड्यंत्र किया, जिससे भारत विरोधी ताकतों ने भारत की जनता को बरगलाने की असफल कोशिश की। बिखरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश में स्थापित 'हिंडनबर्ग रिसर्च' जैसे विदेशी संस्थान ने भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाने का भी प्रयास किया। विभिन्न प्रकार के बेबुनियादी मनगढ़ंत प्रतिवेदन (Report) एवं सूचकांकों का प्रकाशन इसी प्रकार के षड्यंत्रों का भाग है। उदाहरण के लिए 'वैश्विक भूख सूचकांक-2022' (Global Hunger Index 2022) में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश का भारत से अच्छा प्रदर्शन दिखाना, 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2023' (World Press Freedom Index 2023) में तालिबान शासित अफ़गानिस्तान को भारत से अच्छे स्तर पर दिखाना एवं 'वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट-2023' (World Happiness Report -2023) में भारत द्वारा अन्न व आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे ऐसे श्रीलंका और युद्धग्रस्त यूक्रेन और गृहयुद्ध जैसी परिस्थिति से पीड़ित पाकिस्तान जैसे देशों की भारत से अच्छे नंबर पर दिखाने जैसे कुत्सित

प्रयास भी हो रहे हैं। भारतीय छात्रों को कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों में बार-बार प्रताड़ित करना जैसे हाल ही में 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' में एक छात्र के साथ राष्ट्रीयता व वैचारिक मूल्यों के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करना निंदनीय भी है।

भारत के प्रत्येक नागरिक की भूमिका अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण है। कई ऐसी चुनौतियों को लेकर समाज में प्रबोधन की आवश्यकता है जैसा कि हाल ही में आयी 'द केरल स्टोरी' नामक फिल्म से ध्यान में आता है कि किस प्रकार आतंकवाद को पूर्वनियोजित रूप से 'आईएसआईएस' (ISIS) जैसे संगठनों द्वारा भारत की नारी शक्ति के शील व अस्मिता पर प्रहार किए जा रहे हैं।

भारत सरकार सावधानी बरतते हुए वैश्विक षड़यंत्रो से विशेष करके विदेशों से आने वाले धन व संदेहास्पद गतिविधियों में संलिप्त गैर सरकारी संगठनों आदि पर विशेष ध्यान दे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद देशभर के युवाओं से आह्वान करती है की देश-विदेश में चल रहे विभिन्न प्रकार के विमर्श पर दृष्टि रखते हुए समाज में उनके प्रति जागृति लाकर भारत विरोधी षड्यंत्रकारी ताकतों को परास्त करें। ■

राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे का निधन : अभाविप

विज्ञान भारतीय के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जयंत सहस्त्रबुद्धे का गत 2 जून को प्रातः निधन हो गया। पिछले वर्ष 3 सितंबर 2022 को एक सड़क दुर्घटना के बाद से वह उपचाराधीन थे। उनके निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शोक व्यक्त किया है।

अभाविप ने जयंत जी के निधन को राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयता आधारित विचारों के अनुरूप शोध एवं नवाचार की दिशा में कार्य करने हेतु जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने अनेक युवाओं व वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान व वैज्ञानिकों के योगदान पर देश में उल्लेखनीय तथा सार्थक संवाद उत्पन्न करने में सफल भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में आरंभ हुए विज्ञान भारती के अनेक प्रकल्पों का कार्य देशहित में नई दिशा का अन्वेषण करने वाला है।

महाराष्ट्र में 1966 में जन्म लेने वाले जयंत सहस्त्रबुद्धे जी बाल्यकाल से ही प्रखर मेधा के धनी रहे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की नौकरी छोड़ उन्होंने संघ प्रचारक के रूप में देशसेवा का व्रत लिया। माता-पिता की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से उन्हें

भी देशसेवा तथा समाज उत्थान का जो भाव प्राप्त हुआ, वह उनके जीवनकाल में किए गए अनेक सकारात्मक कार्यों में सहज ही प्रदर्शित होता था। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के दायित्व के पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोंकण प्रांत प्रचारक, गोवा विभाग प्रचारक आदि दायित्वों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उनके विचार तथा कार्य लोगों के लिए प्रेरणा के माध्यम के रूप में मार्ग प्रशस्त करेंगे। ■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित प्रस्ताव

स्व-आधारित व्यवस्था निर्माण हेतु समाज हो अग्रसर

भारत की पारंपरिक व्यवस्थाएं धर्म आधारित समाजजीवन का उत्कृष्ट उदाहरण रही हैं। परंतु वर्षों के संघर्ष ने इस व्यवस्था को चोटिल कर दिया, उसका एक विकृत स्वरूप हमारी आजकी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है। राष्ट्रीय विचारों के प्रवाह से स्वाधीनता के पश्चात भारत केंद्रित व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास हुए हैं। 350 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से 'हिंदवी स्वराज्य' की स्थापना हुई जिसका संकल्प स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वनिर्माता बन स्वराज प्रेरित सुशासन रहा, उस अवधारणा को आज पुनः पूर्णरूप से अपनाने की आवश्यकता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा के आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए भी भारत अपनी भूमिका निभाने के पथ पर अग्रसर है।

'स्व' आधारित व्यवस्था निर्माण हेतु अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का स्पष्ट मत है कि -

1. औपनिवेशिक मानसिकता सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता व अखण्डता पर आघात है। इससे बाहर निकलने हेतु युवाओं को अपने कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध व इस मानसिकता से मुक्त समाज जीवन खड़ा करने हेतु आगे आना होगा।
2. पारम्परिक भारतीय व्यवस्था जिसमें न्यायिक विधान, आरक्षी तंत्र, निर्वाचन प्रक्रिया का उद्देश्य लोकहित था, उसने बाह्य ताकतों के प्रभाव से सामंतवादी रूप धारण कर लिया। न्याय का विधान भारतीय मूल चिंतन के विपरीत, आरक्षी तंत्र असंवेदनशीलता तथा निर्वाचन प्रक्रिया लोकहित नीति से जय-पराजय की राजनीति में परिवर्तित हो गयी। आज हमें पुनः अपनी न्यायिक तंत्र को लोकहिताय बनाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ रही कि 18वीं सदी तक भी वैश्विक स्तर पर हमारी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जो प्रमुख रूप से ग्रामीण व कृषि उद्यमिता पर आधारित थी। परंतु औपनिवेशिक काल में हम कमजोर होते गये। यह अमृतकाल भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान कराने के लिए सामूहिक उद्यम करने का अवसर प्रदान कर रहा है। अतः भारत को वैश्विक मंच पर परिवर्तन हेतु स्वदेशी विचारों एवं भाव के साथ उद्यमिता के विकास को संपोषित करने हेतु प्रयोग करने होंगे।
4. शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी प्रारूपों का अंधाधुंध अनुसरण किया गया, जिससे भारत नवाचार से दूर हो गया। नवोन्मेष आधारित प्राचीन शिक्षा प्रणाली अपनाने के साथ तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग एवं प्रकृति केंद्रित विकास सहित आधुनिकीकरण की भारतीय संकल्पना के आधार पर युवाओं को नए प्रतिमान खड़े करने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है।
5. भारत की सांस्कृतिक विरासत, स्वभाषा, पारंपरिक वस्त्र, संगीत, नृत्य कला आदि के द्वारा वैश्विक पटल पर प्रतिनिधित्व करती थी परंतु आक्रांताओं की राष्ट्र को खण्डित करने की नीति ने हमें पाश्चात्य व्यवस्था की ओर धकेल दिया। आज हमें पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को स्मरण करते हुए अपनी समृद्धशाली परंपराओं को पुनर्जीवित कर राष्ट्र के नवोत्थान के लिए परिवार संस्था का दृढ़ीकरण, बंधुता पर आधारित समरस समाज का निर्माण आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने होंगे।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद समाज से आह्वान करती है कि हिंदवी स्वराज्य के 350 वर्ष पूर्ण होने पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सुशासन व्यवस्था का स्मरण कर इसके मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु आगे आए। ■

"आत्म प्रेरणा से पैदा होता है सेवा भाव"

किसी भी मानव में जब सेवा और परोपकार का भाव मौजूद होता है, तो वह एक सरल, स्वस्थ एवं मजबूत समाज के निर्माण में वह अपनी भूमिका का निर्वहन स्वार्थ के बिना करता है। सेवा ही मानव को सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध करवाती है। जीवन में आत्म संतोष एवं आत्म प्रेरणा का भाव भी सेवा कार्य से ही पैदा होता है। छात्र-छात्राओं में सेवा का यही भाव पैदा करने का कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी करता आ रहा है। इसके लिए परिषद का सेवार्थ विद्यार्थी (Student for Seva) प्रकल्प पूरे देश में कार्य कर रहा है। **सेवार्थ विद्यार्थी प्रकल्प की राष्ट्रीय संयोजक मुस्कान आनंद एवं प्रमुख भवानी शंकर ने राष्ट्रीय छात्रशक्ति से हुई विशेष भेंट में प्रकल्प के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की।**

प्रकल्प की राष्ट्रीय संयोजक मुस्कान आनंद ने बताया कि विद्यार्थी की शिक्षा मात्र रोजगार के लिए केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह राष्ट्र एवं समाज निर्माण में अपनी भूमिका का सकारात्मक निर्वहन कर सके। इस विचार को लेकर 2013 में परिषद ने सेवार्थ विद्यार्थी प्रकल्प को प्रारम्भ किया था। इस प्रकल्प के माध्यम से छात्र-छात्राओं में को समाज में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सेवा भाव से प्रेरित छात्र-छात्रा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आते हैं और समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं।

प्रकल्प की राष्ट्रीय संयोजक मुस्कान आनंद के अनुसार सेवार्थ विद्यार्थी प्रकल्प प्रकल्प छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा देने, कौशल केंद्र में सहयोग करने, रक्तदान करने, आपदा या दुर्घटना के समय पीड़ितों की सहायता करने, किसी बड़ी समस्या में सूचना एवं सहायता करने, नगरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगो से जुडी समस्या से जुड़े कार्य करने सहित मानव सेवा के हर आयाम पर कार्य कर रहा है। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि समाज में जिसे भी आवश्यकता है, उसकी सहायता की जाए। सेवा कार्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सेवार्थ विद्यार्थी प्रकल्प के प्रमुख भवानी शंकर ने बताया कि प्रकल्प बस्ती की पाठशाला नाम से गरीब बस्तियों में बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। इसके साथ भी असम में आयी बाढ़ के दौरान प्रकल्प से जुड़े छात्र-छात्राओं ने अपने-अपने तरीके से पीड़ितों की मदद की और पीड़ित किस प्रकार पुनः सामान्य जीवनयापन कर सके, इस दिशा में योगदान दिया। मालवा क्षेत्र में प्रवर्तिका के नाम से एक सर्वेक्षण का कार्य किया, जिसका लक्ष्य विद्यालयों में स्वच्छ बाथरूम की जानकारी लेना था। इसी प्रकार महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में जाकर जनजातियों की मदद में भी प्रकल्प की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोविड महामारी के समय प्रकल्प मुंबई के धारावी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मदद करने में आगे रहा। जागृति कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ऑल इंडिया एनआईटी कॉन्फ्रेंस के साथ ही प्रत्येक दो वर्ष में थिंक इंडिया सम्मेलन का आयोजन भी प्रकल्प द्वारा किया जाता है। प्रकल्प ने एक लाख छात्रों की ऐसी डाइरेक्ट्री भी तैयार की है, जो रक्तदान करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। इसे ब्लड डोनर डाइरेक्ट्री का नाम दिया गया है।

प्रकल्प की राष्ट्रीय संयोजक मुस्कान आनंद कहती हैं कि प्रकल्प सेवा के भारतीय भाव के अनुसार ही सेवा कार्यों में अपना योगदान कर रहा है और हमारे लिए यह कोई अस्थायी कार्य नहीं है। प्रकल्प न तो दया के लिए और न ही किसी को आश्रित बनाने के लिए काम नहीं करता है, यह सभी की जानकारी में होना चाहिए। इसके साथ हमारा लक्ष्य यह भी नहीं होता है कि सेवा की आड़ में धर्मान्तरण को बढ़ावा दिया जाए। प्रकल्प निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहा है और लक्ष्य राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करना है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भावना है और हम भारतीय भातृ भाव को सामने रखते हैं। प्रकल्प हमारे देश के छात्र-छात्राओं को एक ऐसे नागरिक के रूप में तैयार करने के कार्य में जुटा हुआ है, जो सेवा भाव से भारत राष्ट्र के विकास में अपना योगदान निस्वार्थ भाव से कर सके। ■

ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों की सहायता में जुटे अभाविप कार्यकर्ता

ओड़िशा के बालेश्वर जिले के बाहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ता अगर सही समय पर नहीं पहुंचते तो और अधिक लोगों की जान जा सकती थी। भीषणतम रेल हादसे का शिकार हुए लोगों की सहायता के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे। हादसे की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में अभाविप कार्यकर्ता दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए और वहां मची चीख-पुकार के बीच घायलों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले जाना प्रारम्भ कर दिया। साथ ही काफी कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवकों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के साथ मिलकर बचाव कार्य में जुट गए।

अभाविप आयाम सेवार्थ विद्यार्थी के प्रांत संयोजक प्रदीप कुमार मंडल ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही तीन सौ से अधिक अभाविप कार्यकर्ता बचाव और सेवा कार्य में जुट गए। अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए लगभग 400 यूनिट रक्तदान अभाविप कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। घटना के तुरंत बाद अभाविप द्वारा आपदा हेल्पलाइन जारी की गई एवं बचाव कार्य के दौरान पुलिस और चिकित्साकर्मियों का सहयोग किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कटक एवं भद्रक चिकित्सा केन्द्रों में घायलवस्था में भर्ती हुए यात्रियों की समुचित देखभाल की। साथ ही उनके लिए भोजन, पानी, दवाई की व्यवस्था की। पीड़ितों के बीच एक हजार से अधिक खाने के डिब्बे वितरित किए गए।

अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अपांग्शु शेखर शील, प्रदेश अध्यक्ष गार्गी बनर्जी, प्रदेश संगठन मंत्री बैलोचन साहू सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ता चिकित्सा केन्द्रों पर पहुंचकर, घायल यात्रियों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। घायलों और उनके परिवारों की समुचित व्यवस्था के लिए परिषद के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहे। अभाविप के स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि गत 2 जून को प्रातः ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसकी जानकारी मिलते ही वह हादसे वाली जगह पर पहुंच गए थे। इसके बाद उन लोगों ने ट्रेन के दरवाजे खोलकर घायलों को बाहर निकालना शुरू किया। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर, बाइक और कार के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी भी घायल यात्रियों की सहायता में अभाविप कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ■

आर्थिक अभाव नहीं बन सकता है शिक्षा में बाधा

बड़े महानगरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और अभाव के बीच हर वर्ष न जाने कितने बच्चे अपना बचपन खोकर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता हैं? इसका स्पष्ट उत्तर यही मिलता है कि निर्धनता से जूझने वाले परिवार अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिलाने की स्थिति में होते हैं। निर्धनता का एक पहलू यह भी है कि प्रतिभा और योग्यता राष्ट्र और समाज के सामने नहीं आ पाती है। आर्थिक अभाव में शिक्षा से दूर होने वाले बच्चों और उनके माता-पिता की विवशता को देखने और समझने की आवश्यकता भी हर कोई महसूस नहीं करता। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते जो यह प्रयास करते हैं कि प्रतिभा और क्षमता नष्ट नहीं हो और इसके लिए वह अपने स्तर से जो सकारात्मक प्रयास प्रारम्भ करते हैं, वह एक ऐसी मुहिम बन जाती है, जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। **कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के ठाणे निवासी रविंद्र कर्वे के साथ भी हुआ।**

यह कहानी रविंद्र कर्वे के उस प्रयास की है, जो 2010 में उन्होंने शुरु किए थे। ठाणे के टी. जे. एस. बी. सहकारी बैंक की सेवा करते हुए उन्होंने कई बार यह देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते तो हैं, लेकिन परिवार के आर्थिक अभाव उनकी राह में आते हैं। आर्थिक अभाव में दम तोड़ती प्रतिभाओं के लिए कुछ करने की चुनौती को स्वीकार करने के बाद उन्हें पांच ऐसे होनहार बच्चे मिले, जिनके सपनों की राह में आर्थिक अभाव एक बड़ी बाधा थी। यह सभी बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर। इस पांच बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए श्री कर्वे ने अपने मित्रों एवं दानदाताओं की मदद से उनकी आर्थिक मदद की और फिर यही से श्री कर्वे का सफर प्रारम्भ हो गया।

प्रतिभावान बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फीस एवं अन्य आवश्यक खर्च की व्यवस्था के लिए श्री कर्वे ने जो मुहिम प्रारम्भ की, वह धीरे-धीरे महाराष्ट्र के कई जिलों तक फैलती गयी। प्रतिभावान लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का चयन भी एक चुनौती थी, पर यह चुनौती भी श्री कर्वे की राह नहीं रोक पायी। दसवीं कक्षा में 90 प्रतिशत अंक, बारहवीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक लाने वाले गरीब बच्चे धीरे-धीरे उनके संपर्क में आने शुरु हो गए। मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित अन्य रोजगार केंद्रित शिक्षा के लिए 2010 से लेकर 2022 तक अर्थात बारह वर्ष में करीब दो हजार गरीब बच्चों की मदद की गयी।

राष्ट्रीय छात्र शक्ति से हुई विशेष मुलाकात में श्री कर्वे ने बताया कि 2022-2023 के महाराष्ट्र के 35 जिलों में 720 गरीब छात्रों की 4.5 रूपये फीस दी गयी। इसके साथ ही रायगढ़ और ठाणे जिले में जर्जर हो चुके छह स्कूलों का पुनर्निर्माण भी कार्य गया, जिसमें लगभग छह करोड़ रूपये का खर्च आया। दो अन्य स्कूलों का पुनर्निर्माण कार्य जारी हैं। उन्होंने अपने सेवा कार्य के लिए सेवा सहयोग फाउंडेशन का गठन किया, जिसने विद्यार्थी विकास योजना को जन्म दिया। वर्तमान में महाराष्ट्र के हर सरकारी कालेज में ऐसे कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनका खर्च विद्यार्थी विकास योजना द्वारा वहन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिला, तालुका स्तर पर 85 ऐसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो योग्य एवं प्रतिभावान गरीब बच्चों की जानकारी लेने के बाद उनके चयन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। श्री कर्वे बताते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने 1981 तक कार्य किया, जिसके कारण उन्होंने गरीब बच्चों की समस्या को स्वयं महसूस किया था। इससे होने प्रेरणा मिली थी और बाद में उन्होंने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया। विद्यार्थी विकास योजना के लिए किसी से कोई भी धन सिर्फ बैंक खाते में ही लिया जाता हैं और विद्यार्थियों की मदद भी बैंक खाते के माध्यम से की जाती है। योजना में आर्थिक मदद देने में विख्यात क्रिकेट खिलाडी सचिन तेंदुलकर सहित महाराष्ट्र की कई बड़ी हस्तियां जुडी हुई हैं। वर्तमान में यह योजना महाराष्ट्र से बाहर निकल कर नौ राज्यों तक पहुंच चुकी है और प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरे देश विद्यार्थी विकास योजना के माध्यम से प्रतिभाओं और योग्यता वाले गरीब बच्चों के सपनों की उड़ान में आर्थिक अभाव आड़े नहीं। श्री कर्वे की आने दिया जाए। मुहिम से जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वह भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सभी का लक्ष्य यही है कि आर्थिक अभाव शिक्षा में बाधा नहीं बनना चाहिए, जिससे एक ऐसे सशक्त समाज का निर्माण हो, जो भारत को सक्षम और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करे। ■

झारखंड अभाविप द्वारा जनजातीय छात्रों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), झारखण्ड ने राज्य के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समाज के विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय एक्सपोजर विजिट अभियान का आयोजन किया। एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के उद्‌घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने कहा कि ऐसी परंपरा से ही सभी धर्मों का जन्म और विकास हुआ है। विद्यार्थी परिषद ही एक मात्र ऐसा छात्र संगठन है, जो छात्रों में सर्वगुण का संचार करता है। यह संगठन झारखंड जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। देश में जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से निकाल कर उच्च शिक्षा का संचार कराने के लिए अभाविप द्वारा एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान प्रत्येक वर्ष चलेगा।

इस सम्बन्ध में अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद नायक ने बताया कि जनजाति समाज के विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा और समाज के विविध क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए. उनके मन में आत्मविश्वास जगाने हेतु एक प्रयास है। झारखंड की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय समाज के वीरों से छात्रों को प्रेरणा लेना चाहिए।

अभाविप के अखिल भारतीय जनजातीय कार्य सह प्रमुख प्रमोद राउत ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यार्थियों को करियर के साथ-साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे ले जाने की प्रेरणा दी। एक्पोजर विजिट कार्यक्रम के माध्यम से सुदूर क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय छात्रों के व्यक्तित्व को निखारना एवं उनकी प्रतिभा को उचित मंच दिलाना है। एक्पोजर विजिट के तहत छात्रों को आईआईटी, एनआईटी जैसे शैक्षिक संस्थान का भ्रमण कराना एवं वहां प्राध्यापकों एवं अध्येताओं से संवाद स्थापित कर उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी प्रकार खेल में रुचि रखने वाले छात्रों को उस क्षेत्र के महारथियों से मिलाना, संवाद स्थापित करना, उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं से परिचित कराना, विभिन्न स्पोर्टस कंप्लेक्स, इंडोर-आउटडोर स्टेडियम का भ्रमण कराना आदि शामिल है, ताकि वह इस दिशा में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके।

अभाविप झारखंड प्रांत संगठन मंत्री राजीव रंजन के अनुसार पहले चरण में राज्य के 24 जिलों से 50 जनजातीय छात्रों को रांची लाया गया। उन्हें गत 15 मई से 17 मई तक उन्हें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एनआईएफएफटी जैसे विभिन्न संस्थानों का भ्रमण कराया गया। इसके बाद संवाद कार्यक्रम हुआ। झारखंड के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के दिनेश चंद्र गुप्ता के अनुसार छात्रों को भ्रमण कराना, अभाविप की एक अच्छी पहल है। छात्रों को आईआईटी में पढ़ाई के साथ प्रयोग करने पर अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा के साथ वास्तविक प्रयोग से छात्रों को विषय बेहतर ढंग से समझ में आता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय (झारखंड) के कुलपति डॉ. क्षिति भूषण दास ने भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए छात्रों को आगे बढ़ने के लिए कैंपस में भ्रमण कराने को एक अच्छी पहल बताया है। ■

श्मशान के करीब पहुंच गई है बंगाल की शिक्षा व्यवस्था : मिथुन चक्रवर्ती

पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। श्री चक्रवर्ती ने गत 2 जून को को कोलकाता में दक्षिण बंगाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा आयोजित लीड बंगाल स्टूडेंट्स कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए अभाविप कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए।

पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग की स्थिति पर पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था श्मशान के करीब पहुंच गयी है। अब यहां का सारा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है। सबका मनोबल टूट गया है। यदि आप एक राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, तो शिक्षा बंद कर दें। बंगाल की शिक्षा व्यवस्था का सुधार करने के लिए छात्रों को आगे आना होगा। वह स्वयं कई छात्र आंदोलनों में शामिल रहे हैं। इसलिए वर्तमान में छात्रों को एकजुट होने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

ममता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य में यही हुआ है। सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने पैसे लेकर जनता को नौकरी दी। यह बहुत सावधानी से किया जा रहा है, लेकिन बंगाल की जनता ने इससे बड़े मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ी है और जनता इसके विरुद्ध भी खड़ी होगी। बुद्धिजीवियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता के बुद्धिजीवी बिक चुके हैं। यदि आत्मा बिक जाती है, तो उसे वापस नहीं पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह भाषण नहीं दे सकते हैं, लेकिन वह एक डायलॉग दे सकते हैं कि वह नेता नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता हैं। अगर आप जीना चाहते हैं, तो लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। यह पूछे जाने पर कि सफलता का पैमाना क्या है? उन्होंने कहा कि आईने में अपना चेहरा साफ देखें। यही सफलता है क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता है।

कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री नाम में ममता है, लेकिन उनके दिल में ममता का अभाव है। बंगाल का समृद्धशाली इतिहास रहा है।

पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्ट और अब ममता सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य का भविष्य अंधेरे के गर्त मे जा चुका है। राज्य की जनसंख्या बदल चुकी है। ममता सरकार की कुनीतियों के कारण बंगाल के लोग अभाव में जी रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रभाव में हैं। शिक्षा क्षेत्र में बड़े-बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार को आज पूरा जनमानस देख रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता दीदी, जिन्हें प्रदेश की सेवा करनी चाहिए थी, वह जनता की सेवा करने के स्थान पर बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को मेवा देने का काम कर रही है।

युवाओं को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि युवा का उल्टा वायु होता और हमें वायु की गति से इस प्रदेश की भलाई के जुटना है। यहां की समस्या केवल इस प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। इसी को ध्यान में रखकर अभाविप ने लीड बंगाल कार्यक्रम का आयोजन किया। सरकार की कुनीतियों के लिए विरुद्ध यह शंखनाद है। आप सभी को कमर कसकर बंगाल में व्याप्त भय, भ्रष्टाचार, आंतक और तुष्टीकरण के खिलाफ आगे आना होगा।

जानकारी हो कि दक्षिण बंगाल अभाविप द्वारा गत 2 जून को कोलकाता के ईजेडसीसी, साल्ट लेक में लीड बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्क्लेव नाम से एक छात्र संगोष्ठी आयोजन किया गया था। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अभाविप महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल उपस्थित रहे। संगोष्ठी में एक संवाद सत्र यानी प्रश्नोत्तरी का था, जिसमें छात्रों ने मिथुन चक्रवती से प्रश्न पूछे और उसके उत्तर जाने। मिथुन ने छात्रों के प्रश्नों का अपने बेबाक अंदाज मे जवाब दिया। अभाविप प्रदेश मंत्री संगीत भट्टाचार्य के अनुसार कॉन्क्लेव में 12 सौ से अधिक छात्रों ने सहभागिता की। आने वाले समय में इस तरह की और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद नायक, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अपांग्शु शेखर शील, प्रांत अध्यक्ष डॉ. पवित्र देवनाथ, प्रांत संगठन मंत्री सप्तऋषि सरकार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ■

अभाविप के संघर्षों ने लाया रंग, जेएनयू में चार साल बाद होंगे छात्रसंघ चुनाव

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में विद्यार्थियों की समस्याओं और अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(अभाविप) जेएनयू के कार्यकर्ताओं ने गत 2 जून को विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव किया। घेराव के बाद विवि प्रशासन ने परिषद की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

अभाविप जेएनयू इकाई अध्यक्ष उमेश चंद्र अजमीरा ने बताया कि अकादमिक सत्र 2023-24 के प्रारम्भ होने के छह सप्ताह के अंदर ही जेएनयू प्रशासन छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है। यह चुनाव लगभग चार वर्ष बाद होंगे। वहीं, अगर किसी स्थिति में सत्र शुरु होने के छह सप्ताह के अंदर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और किसी अन्य केंद्रीय विवि में इसी स्थिति में छात्र संघ चुनाव होता है तो जेएनयू प्रशासन भी उन्हीं शर्तों पर चुनाव कराएगा। जेएनयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया अगले 10 से 12 दिनों में प्रारम्भ हो जाएगी। स्नातक में आयुर्वेद बायोलाजी का जो कोर्स पिछले तीन वर्षों से जेएनयू में बिना यूजीसी की मान्यता के जारी है, उसके लिए भी इसी सप्ताह से प्रयास प्रारम्भ हो जाएंगे। प्रबंधन में जो पीएचडी बंद कर दी गई थी, उसे भी अगले वर्ष से पुनः प्रारम्भ किया जाएगा। बराक छात्रावास आवंटन के साथ-साथ छात्रावास नवीनीकरण, पुस्तकालय अपग्रेड, मेस और कैंटीन शुल्क में वृद्धि की समस्या के साथ ही फैलोशिप का भी समय पर वितरण होगा। ■

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अभाविप का विरोध-प्रदर्शन

इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) में अनियमितता, प्रवेश परीक्षा, परिणाम प्रक्रिया में सुधार इत्यादि मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। इंदौर सहित अलग-अलग जिलों से आए हजारों छात्रों और अभाविप के कार्यकर्ताओं ने डीएवीवी आरएनटी मार्ग परिसर का घेराव भी किया।

अभाविप राष्ट्रीय मंत्री वीरेन्द्र सोलंकी के अनुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षा का केन्द्र है। प्रदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते हैं। परंतु विगत कुछ समय से विश्वविद्यालय में अनियमतताएं, अव्यवस्थाएं एवं विद्यार्थियों की समस्याएं चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी आक्रोश है।

गत 14 जून को हुए धरना-प्रदर्शन के बाद अभाविप कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो, अगले चरण में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अभाविप की मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी पहल की है और कई मांगों के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करने का फैसला लिया है। डीएवीवी प्रशासन जल्द ही कुलपति हेल्पलाइन शुरू करेगा। क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रभारियों की बैठक, रिव्यू, रिवैल्युएशन और एटीकेटी की फीस के मामले में भी जल्द निर्णय लेने की बात कही गई है।

अभाविप की 23 सूत्रीय मांग

अभाविप ने प्राध्यापकों की नियुक्ति, वार्षिक कैलेंडर, विश्वविद्यालय परिसर में नशाखोरी, पेपर लीक मामला, पीएचडी प्रवेश परीक्षा, महाविद्यालय को मान्यता में पारदर्शिता, महंगी शिक्षा, एटीकेटी परीक्षा शुल्क में कमी, रीजनल सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त करने जैसी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी हैं। साथ ही अभाविप ने विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन करने पर लगाए गए प्रतिबंध को भी वापस लेने, शिक्षकों की भर्ती के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने, छात्रों की समस्याओं के निदान के लिए नोडल सेंटर प्रारंभ करने, प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर विश्वविद्यालय के वार्षिक अकादमिक कैलेंडर का पालन सही ढंग से करने, विश्वविद्यालय में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन की विसंगतियों को दूर करने, परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं की रोकथाम, कोड 28 का अनिवार्य रूप से पालन करने, परीक्षा कॉपी खरीद में हुई धांधली पर उचित कार्रवाई करने, विश्वविद्यालय में नशे की रोकथाम, विद्यार्थियों की के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए वीसी हेल्पलाइन जारी करने और लॉ डीन की नियुक्ति जल्द करने की मांग भी विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' जून 2023 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद, अभाविप ने खोला मोर्चा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परिणाम चयन सूची जारी होने के बाद से विवादों के घेरे में आ गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीजीपीएससी परिणाम में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। अभाविप छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री मनोज वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें शिक्षा का नहीं भ्रष्टाचार का बोल-बाला है। गत 11 मई को प्रकाशित सीजीपीएससी परीक्षा परिणाम को देखने से स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार दिखता है। टॉप-20 स्थान तक बड़े अधिकारियों और व्यापारियों के रिश्तेदार चयनित हुए हैं। इस शर्मनीय घोटाले के विरुद्ध विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया। गत 18 मई को मुख्यमंत्री आवास का जब घेराव किया तो मुख्यमंत्री के इशारे पर अभाविप कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया।

प्रदेश मंत्री ने कहा कि परिषद इन लाठियों से डरने वाली नहीं है। घोटाले की जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक हमारा विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अभाविप के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदनजी को ज्ञापन सौपा और उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग की।

लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की निकाली शव यात्रा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीजीपीएससी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सोनवानी की शवयात्रा निकाली। इस कड़ी में रायपुर के बूढ़ातालाब धरना स्थल में पुलिस और अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने विरोध-प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

टॉप-20 में नेताओं के रिश्तेदार, अधिकारी और कारोबारियों के बच्चे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और प्रतियोगियों का दावा है कि सीजीपीएससी के परिणाम में टॉप-20 में शामिल अभ्यर्थी में कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों के साथ ही अधिकारी और कारोबारियों के बच्चे हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रदेश के होनहार प्रतियोगियों की जगह सूची में आयोग के चेयरमैन के दत्तक पुत्र के साथ ही अन्य रिश्तेदारों का चयन किया गया, जो उनके साथ छलावा है। अभाविप का कहना है कि मेधा (मेरिट) सूची पर प्रथम आए और 20वें नंबर पर आए उम्मीदवार आपस में भाई-बहन हैं। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर चयनित उम्मीदवार कांग्रेस नेता की बेटी है।तीसरे व चौथे स्थान पर चयनित उम्मीदवार पति-पत्नी हैं और रसूखदार परिवार से हैं। मेधा सूची में 9वें व 12वें स्थान पर चयनित उम्मीदवार एक आईएएस अधिकारी के बच्चे हैं। मेरिट में 11वें स्थान पर काबिज उम्मीदवार डीआईजी की बेटी है। सीजीपीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों ने अपना नौकरी का आशियाना बसा लिया है, जिसमें नितेश सुनवानी का पुत्र डिप्टी कलेक्टर बना है। साहिल सोनवानी (भतीजा) डीएसपी एवं सुनीता जोशी श्रम पदाधिकारी सोनवानी जी की भांजी ने सीजीपीएससी टॉप-20 में स्थान पाया है। वहीं सरनेम को हर एक के नाम से छिपाया गया है।

अभाविप ने लगाई सीजीपीएससी की दुकान

प्रतियोगियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हुए पहुंच और पैसे के दम पर पद देने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सीजीपीएससी की दुकान खोलकर अलग-अलग पदों के लिए बोली लगायी। अभाविप का कहना है सीजीपीएससी में कुछ इसी तरह पदों की बोली लगाकर सूची जारी की गई। अभाविप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर सीजीपीएससी घोटाले के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता 75 लाख रुपये में डिप्टी कलेक्टर, 65 लाख रूपए में डीएसपी लिखे बोर्ड लेकर सड़क पर उतरे। हाथों में तख्ती लिए, ठेले पर गोबर के कंडे और प्याज लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ■

छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले के विरूद्ध दुकान लगाकर विरोध–प्रदर्शन करते अभाविप कार्यकर्ता

देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर में व्याप्त अनियमितता के विरूद्ध अभाविप का विरोध–प्रदर्शन

RNI NO.: DELBIL/2017/73636 POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की झलकियाँ